https://www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

'मजबूत है देश की अर्थव्यवस्था'

वर्ष-12, अंक-20 16-31 अक्टूबर, 2017 (पाक्षिक) ₹20

कार्यकर्ताओं के बलिदान को नमन!

जीएसटी: छोटे, सर्राफा कारोबारियों, किसानों और आम लोगों को बड़ी राहत

मनुष्य या मशीन

'आदिवासी देशभक्तों को पुष्पांजलि नहीं, कार्यांजलि दे रही है भाजपा'

जेहादी-वामपंथी आतंक के खिलाफ पयान्नूर (कन्नूर), केरल से जनरक्षा यात्रा का आरंभ करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, साथ में अन्य वरिष्ठ भाजपा नेतागण। नीचे यात्रा की झलकियां

पिलथारा की तरफ बढ़ते हुए

महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए

बलिदानियों के परिवार-जनों से मिलते हुए

बलिदानियों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए

पिलथारा में विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए

सरदार पटेल के जन्मस्थान करमसद (गुजरात) से 'गुजरात गौरव यात्रा' का शुभारम्भ करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, साथ में- गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी एवं अन्य नेतागण

करमसद में श्री अमित शाह का स्वागत करते गुजरात भाजपा नेतागण

गौरव यात्रा के दौरान जनाभिवादन स्वीकार करते श्री अमित शाह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन : +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स : +91(11) 23387887

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in
mail@kamalsandesh.com

वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **पार्टी कार्यकर्ताओं की शहादत कभी व्यर्थ नहीं जायेगी : अमित शाह**

जनरक्षा यात्रा केवल केरल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं है, बल्कि देश भर में फैले हुए 11 करोड़ पार्टी कार्यकर्ताओं की यात्रा है। उन्होंने कहा कि हमें यह जनरक्षा यात्रा लेकर इसलिए निकलना पड़ रहा है, क्योंकि...

वैचारिकी

मनुष्य या मशीन 16

श्रद्धांजलि

सरदार वल्लभ भाई पटेल / भैरोंसिंह शेखावत 18

लेख

'आदिवासी देशभक्तों को पुष्पांजलि नहीं, कार्यांजलि दे रही है भाजपा' 20

जल पर संवेदनशील बने समाज 22

अन्य

पेट्रोल और डीजल पर बेसिक उत्पाद शुल्क 2 रुपये प्रति लीटर कम 13

भारत में शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी 15

सेवाओं का एकीकरण मेरी प्राथमिकता: रक्षा मंत्री 17

आज स्वच्छता अभियान बना एक आंदोलन : नरेन्द्र मोदी 19

मजबूत है देश की अर्थव्यवस्था : नरेंद्र मोदी 24

जनता को जमानती सरकार से मुक्ति मिलनी चाहिए : नरेन्द्र मोदी 32

स्थायी स्तंभ

सोशल मीडिया से 04

पत्र-पत्रिकाओं से 33

स्फुट विचार 33

संगठनात्मक गतिविधियां

09 **'विकास क्रांति के गौरव को जन-जन तक पहुंचाना है'**

'हूं विकास छू, हूं गुजरात छू' के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी 1 अक्टूबर से...

28 **'हमें विश्व में सबसे तेज गति से बढ़नेवाली अर्थव्यवस्था बनने से कोई रोक नहीं सकता'**

केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के...

सरकार की उपलब्धियां

12 **जीएसटी: छोटे, सर्राफा कारोबारियों, किसानों और आम लोगों को बड़ी राहत**

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री...

14 **3.7 लाख करोड़ रुपये हुआ प्रत्यक्ष कर राजस्व संग्रह**

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने 29 सितम्बर को कहा कि वित्त मंत्रालय...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

हम स्वच्छ भारत मिशन पर जितना अधिक बल देंगे, हमें उसका लाभ पर्यटन को बढ़ावा देने में मिलेगा।

@AmitShah

देश में दो प्रकार के मॉडल हैं, एक नेहरू-गांधी परिवार का विकास को अवरुद्ध करने वाला मॉडल और दूसरा विकास का प्रतीक मोदी मॉडल।

@rajnathsingh

एमपीएफ योजना स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ी आतंरिक सुरक्षा योजना है, जिसका कुल परिव्यय 25060 करोड़ रुपए है।

@ArunSinghbjp

जन रक्षा यात्रा केरल में राजनीतिक हिंसा के विरुद्ध देश के ११ करोड़ भाजपा सदस्य केरल के कार्यकर्ताओं के संघर्ष के साथ हैं।

facebook

महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन के लिए शुरू हुई भामाशाह योजना देश की सबसे बड़ी सीधे लाभ हस्तांतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर-DBT) की योजना है, जिसमें अब तक 28 करोड़ से अधिक ट्रांजेक्शन हुए हैं और इन ट्रांजेक्शनों के जरिये 10 हजार करोड़ रूपये से अधिक की राशि वितरित हो चुकी है, जो एक रिकॉर्ड है। **— वसुंधरा राजे**

पंतनगर विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय किसान मेले व कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। साथ ही 3 किसान रथों को रवाना किया। किसानों की स्थिति सुधारने की दिशा में हमने कई कदम उठाए हैं। चकबंदी अपनाकर कृषि जोत को व्यवस्थित किया जा रहा है। किसानों को 2% ब्याज दर पर 1 लाख तक का कर्ज देकर उन्हें उन्नत कृषि के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। **— त्रिवेंद्र सिंह रावत**

केंद्र सरकार ने नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोमोशन स्कीम (NAPS) के तहत छह से अधिक कामगार रखने वाली छोटी औद्योगिक इकाइयों में भी कम से कम 2.5 फीसद प्रशिक्षु कामगार (अप्रेंटिस) रखना अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले से देश भर में युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। **— सुशील कुमार मोदी**

आतंकी राजनीति के विरुद्ध 'जन रक्षा यात्रा'

केरल में माकपा के आतंकी राजनीति के विरुद्ध पदयात्रा का शुभारंभ कर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जैसे ही जनसंघर्ष का बिगुल बजाया, पयान्नूर की सड़कें पदयात्रा में भाग लेने आये लोगों के सैलाब से भर गईं। यह पहली बार है कि माकपा के नेतृत्व में बनी गठबंधन सरकार को इतनी कड़ी चुनौती मिल रही है। लोग भारी संख्या में हिंसा, हत्या, खूनखराबा और आतंक के विरुद्ध सड़कों पर उतर रहे हैं। जिस जघन्य तरीके से भाजपा–संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, उससे यह प्रमाणित होता है कि विरोध के किसी भी स्वर को दबाने के लिये कम्युनिस्ट राजनीतिक हिंसा में विश्वास रखते हैं। 'वर्ग–शत्रु' के सफाये के नाम पर कम्युनिस्टों का हिंसा से इतना अटूट लगाव रहा है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में जिस भी राज्य में इनका शासन रहा, लोगों को भयानक हिंसा का सामना करना पड़ा। प. बंगाल और त्रिपुरा में भी सत्ता की भूख तथा अधिनायकवाद ने इन्हें रक्तपिपासु बना दिया। भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं से प्रेरणा लेने के स्थान पर ये स्टालिन, माओ और पॉलपॉट जैसे भयानक नरसंहारों को अंजाम देने वाले तानाशाहों को अपना आदर्श बना लिया, जिससे भारत में भी हिंसा की राजनीति इनका मूलमंत्र बन गया। इसका परिणाम यह हुआ है कि त्रिपुरा में इनके पैर उखड़ रहे हैं और केरल में अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना भाजपा के रूप में कर रहे हैं। यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया का एक वर्ग देश में चल रहे कम्युनिस्ट हिंसा पर प्रश्न खड़े करने से कतराता रहा है। इसी प्रकार का रवैय्या तब देखा गया जब प. बंगाल में कम्युनिस्ट अपने सत्ता के नशे में खुलेआम अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने का षड्यंत्र करते थे। आज भी तापसी मलिक जैसों का बलात्कार एवं जघन्य हत्या लोग भूले नहीं हैं और इस जैसे अनगिनत संगीन मामलों का संज्ञान नहीं लिया जा सका है।

> हाल में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन से अब यह स्पष्ट है कि कम्युनिस्टों की राह अब प्रदेश में बहुत कठिन हो चुकी है। जहां माकपा ने इस चुनौती का जवाब हिंसा हत्या और खून–खराबा से देना शुरू किया है, वहीं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कम्युनिस्टों की हिंसा और हत्या की राजनीति का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने को कृतसंकल्पित है।

हालांकि नंदीग्राम और सिंगूर में मचे लोमहर्षक तांडव से कम्युनिस्ट पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं, परन्तु इनके शासन में हुए राजनीतिक हिंसा की पूरी पड़ताल होनी बाकी है। केरल में केवल 2001 से अब तक 120 से अधिक भाजपा–संघ कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या कम्युनिस्टों द्वारा की जा चुकी है। पिछले वर्ष इनके सत्ता में आते ही राजनीतिक हिंसा में तेजी आई है तथा केरल में अनेक भाजपा–संघ के निर्दोष कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्याएं हुई हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि सत्ता तथा शासन के संरक्षण में ये अपने राजनैतिक विरोधियों को कुचल देना चाहते हैं। हाल में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन से अब यह स्पष्ट है कि कम्युनिस्टों की राह अब प्रदेश में बहुत कठिन हो चुकी है। जहां माकपा ने इस चुनौती का जवाब हिंसा, हत्या और खून–खराबा से देना शुरू किया है, वहीं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कम्युनिस्टों की हिंसा और हत्या की राजनीति का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने को कृतसंकल्पित है।

अमित शाह द्वारा शुरू किये गये 'जनरक्षा यात्रा' तथा विभिन्न प्रदेश राजधानियों में चल रहे पदयात्रा से कम्युनिस्टों का भयावह चेहरा अब जनता के सामने आ रहा है। पूरे देश में इन यात्राओं में भारी जनभागीदारी से यह स्पष्ट है कि केरल और त्रिपुरा में अब इनके दिन बस गिनती के रह गये हैं। यह कम्युनिस्टों के हिंसा, लोकतंत्र–विरोधी तथा तानाशाही प्रवृत्ति में अटूट विश्वास का ही परिणाम है कि पूरी दुनिया से इनका सफाया हो चुका है। जहां भी ये किसी प्रकार से सत्ता में बने हुए हैं, अपने अस्तित्व की अंतिम संघर्ष में उलझे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इन्हीं कारणों से जिस पार्टी को '1917 की कथित बोलशेविक क्रांति' का शताब्दी वर्ष अभी मनाना चाहिये था, अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। जैसे–जैसे 'जनरक्षा यात्रा' आगे बढ़ रही है और जनभागीदारी इसमें बढ़ती जा रही है, कम्युनिस्टों के पांव उखड़ते जा रहे हैं। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

पार्टी कार्यकर्ताओं की शहादत कभी व्यर्थ नहीं जायेगी : अमित शाह

जनरक्षा यात्रा केवल केरल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं है, बल्कि देश भर में फैले हुए 11 करोड़ पार्टी कार्यकर्ताओं की यात्रा है। उन्होंने कहा कि हमें यह जनरक्षा यात्रा लेकर इसलिए निकलना पड़ रहा है, क्योंकि जब से केरल में सीपीआई (एम) गठबंधन की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 13 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 3 अक्टूबर को पयान्नूर, केरल में भाजपा एवं विचार परिवार के कार्यकर्ताओं पर लगातार हो रहे हिंसक हमलों के खिलाफ 'जनरक्षा यात्रा' की शुरुआत की। इसके पहले भाजपा अध्यक्ष ने थलिप्परंबा स्थित राज राजेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना की और भगवान् शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात् उन्होंने भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और इसके बाद उन्होंने शहीद भाजपा एवं विचार परिवार के कार्यकर्ताओं के परिवारजनों से मुलाक़ात की। ज्ञात हो कि 15 दिनों की यह जनरक्षा यात्रा आज पयान्नूर से शुरू होकर 17 अक्टूबर को तिरुअनंतपुरम से समाप्त होगी।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जनरक्षा यात्रा केवल केरल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं है, बल्कि देश भर में फैले हुए 11 करोड़ पार्टी कार्यकर्ताओं की यात्रा है। उन्होंने कहा कि हमें यह जनरक्षा यात्रा लेकर इसलिए निकलना पड़ रहा है, क्योंकि जब से केरल में सीपीआई (एम) गठबंधन की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 13 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं के विरोध में सत्याग्रह के रूप में जनरक्षा यात्रा लेकर निकलने वाले हैं। उन्होंने कहा

कि आज से लेकर आने वाली 17 तारीख तक यह यात्रा पयान्नूर से लेकर तिरुअनंतपुरम तक होने वाली है और हर दिन केरल की जनता को वामपंथी हिंसा के खिलाफ एकजुट करने वाली है। उन्होंने कहा कि यात्रा के हर दिन कोई-न-कोई भाजपा के मुख्यमंत्री, केन्द्रीय मंत्री और संगठन के पदाधिकारी केरल के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे शहीद कार्यकर्ताओं की याद में पैदल मार्च करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कल से लेकर 16 अक्टूबर तक दिल्ली में भी हर दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदयात्रा निकालेंगे और सीपीएम कार्यालय के बाहर धरना देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और असम से लेकर गुजरात तक पूरे देश में हर राज्य की राजधानी में भी एक-एक दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पैदल मार्च निकालकर कम्युनिस्ट हिंसा के खिलाफ सत्याग्रह करने वाले हैं।

श्री शाह ने कहा कि हम जनरक्षा यात्रा कन्नूर जिले से इसलिए निकाल रहे हैं, क्योंकि यह केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री का जिला है, कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी का जिला है और राज्य में लेफ्ट गठबंधन की सरकार बनने के बाद इसी जिले में सबसे ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या और हिंसा की घटनाएं हुई है। उन्होंने कहा कि मैं आज केरल की जनता को यह भी याद दिलाने आया हूं कि केरल की भूमि शांति की भूमि रही है, समाज सुधार की भूमि रही है, यहां पर कभी आदि शंकराचार्य, स्वामी श्री नारायण गुरुदेव, शुभानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी जैसे मनीषी हुए हैं, जिन्होंने यहां पर समाज सुधार एवं जनचेतना का आंदोलन चलाया था। उन्होंने कहा कि शांति और सद्भाव की यह पावन भूमि रक्तरंजित क्यों हो गई है? यह परिवर्तन कैसे आया है? उन्होंने कहा कि जब से केरल में कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हुआ है, तब से यहां राजनीतिक हिंसा की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ केरल, बल्कि जहां-जहां कम्युनिस्टों का शासन रहा, जहां-जहां वामपंथी पार्टी मजबूत हुई, उन सभी राज्यों में राजनीतिक हिंसा का निरंतर दौर चला है चाहे वह पश्चिम बंगाल हो, त्रिपुरा हो या फिर केरल क्योंकि इन सभी जगहों पर लंबे समय तक कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा है। उन्होंने कहा कि केरल में हिंसा का दौर कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि केरल में जब-जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आती है, हिंसा का दौर शुरू हो जाता है, अब तक भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 120 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अकेले मुख्यमंत्री पिन्नाराई विजयन के जिले में हमारे 84 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को शहीद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं आज इस मंच से मुख्यमंत्री विजयन जी से पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, इन 84 कार्यकर्ताओं के खून का धब्बा किसके कपड़े पर लगा है, आपके पास यदि इसका कोई जवाब नहीं है तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि इन सारी निर्मम हत्याओं की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री विजयन की है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मैं देश भर में फैले हुए ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस से भी पूछना चाहता हूं, केरल में जब हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, तब आपको असहिष्णुता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है, तब आप क्यों अपनी आंखें मूंद लेते हैं, क्यों तब दिल्ली में जुलूस नहीं निकलता, क्यों तब कैंडल मार्च नहीं निकलता, जब हमारे शहीद कार्यकर्ता भाई रामचंद्रन की बेटी देवांगना वंदे मातरम् गाते वक्त अपने पिता को याद करते हुए भूल जाती है तब क्यों आपकी आंखों में पानी नहीं आता? उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस को सेलेक्टिव असहिष्णुता का ढोंग बंद करना पड़ेगा और शांति में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को हिंसा के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं ह्यूमन राइट्स के सभी चैम्पियन से अपील करना चाहता हूं कि आप इस मान्यता को अपने दिमाग से निकाल दें कि लाल रंग की हिंसा हिंसा नहीं होती। उन्होंने कहा कि हिंसा हिंसा होती है, चाहे कोई भी करे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 120 से अधिक कार्यकर्ता केरल में शहीद हो गए हैं, आखिर क्या दोष था उनका, वे तो अपनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे थे, वे तो भारत माता के कल्याण के लिए काम कर रहे थे, वे तो केरल में एक राष्ट्रवादी सोच को लेकर आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय

जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या पर मुख्यमंत्री पिन्नाराई विजयन की चुप्पी उनकी निष्ठा पर कई सवाल खड़े करती है।

श्री शाह ने कहा कि मैं आज शहीद परिवारों के परिवारजन के साथ मुलाक़ात कर रहा था, उनसे परिचय प्राप्त कर रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए एक ओर तो गर्व भी हो रहा है, वहीं दूसरी ओर अपार दुःख भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि कई परिवार ऐसे हैं, जिनके एक ही परिवार में से दो-दो, तीन-तीन लोगों की हत्या कर दी गई और चौथा सदस्य भारतीय जनता पार्टी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता शहीद पार्टी कार्यकर्ताओं को याद करके, उनसे प्रेरणा लेते हुए हिंसा के खिलाफ लड़ाई को लड़ने के लिए कटिबद्ध है, पार्टी कार्यकर्ताओं की शहादत कभी व्यर्थ नहीं जायेगी।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कुछ ही दिन पहले अभी-अभी पंडित

जनसभा, पिलथारा (केरल)

'लाल आतंक के खिलाफ लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ें'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 3 अक्टूबर को पयान्नूर, केरल में भाजपा एवं विचार परिवार के कार्यकर्ताओं पर लगातार हो रहे हिंसक हमलों के खिलाफ जनरक्षा यात्रा की शुरुआत की। ज्ञात हो कि 15 दिनों की यह जनरक्षा यात्रा आज पयान्नूर से शुरू हुई है, जो 17 अक्टूबर को तिरुअनंतपुरम से समाप्त होगी। भाजपा अध्यक्ष ने पयान्नूर से एझिलोड होते हुए पिलाथारा तक लगभग 9 किलोमीटर लंबी पदयात्रा का नेतृत्व किया। पदयात्रा करने के बाद उन्होंने पिलाथारा में एक जनसभा को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं का हिंसा की राजनीति के सामने केरल की जनता को लोकतांत्रिक तरीके से संगठित करने का आह्वान किया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने देश से जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करने का काम किया है और आज केरल के हजारों कार्यकर्ताओं ने कम्युनिस्ट हिंसा की राजनीति को समाप्त करने की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में सालों से कम्युनिस्ट पार्टियों ने हिंसा की राजनीति चलाई है, लेकिन अब देश की जनता हिंसा की राजनीति को किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हिंसा की राजनीति को समाप्त करने की मुहिम का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना चाहिए।

श्री शाह ने कहा कि यह जनरक्षा यात्रा केरल में पयान्नूर से त्रिवेंद्रम तक चलने वाली है, यह यात्रा देश भर में चलने वाली है और देश की राजधानी दिल्ली में भी चलने वाली है। उन्होंने कहा कि यह जनरक्षा यात्रा जिस दिन त्रिवेंद्रम में समाप्त होगी, उसी दिन वामपंथी पार्टियों की हिंसा की राजनीति के पतन की भी शुरुआत हो जायेगी। उन्होंने केरल की जनता से अपील करते हुए कहा कि आगामी 17 अक्टूबर तक चलने वाली इस जनरक्षा यात्रा का समर्थन कीजिये और हिंसा की राजनीति करने वाली कम्युनिस्ट पार्टियों को केरल से उखाड़ फेंकने में भारतीय जनता पार्टी की मदद कीजिये। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश में पॉलिटिक्स ऑफ़ परफॉरमेंस की राजनीति की शुरुआत की है। विकास की राजनीति की शुरुआत की है और पूरा देश इस राजनीति को स्वीकार कर रहा है, आज देश के 80% भू-भागों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने कहा कि आज जनरक्षा यात्रा का पहला दिन समाप्त हुआ है, आगामी 17 अक्टूबर तक यह यात्रा चलने वाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और केरल की जनता का काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि कम्युनिस्ट सरकार को हम केरल से उखाड़ कर फेंक नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं केरल भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से अपील करना चाहता हूं कि वे पूरे राज्य में फ़ैल जाएं और हिंसा की राजनीति के सामने केरल की जनता को लोकतांत्रिक तरीके से संगठित करें एवं लाल आतंक के खिलाफ मोर्चा लेकर पूरे दमखम के साथ लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ें और केरल में परिवर्तन करें।

दीनदयाल जन्मशती वर्ष समाप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती वर्ष में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देश के कोने-कोने में करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। देश भर में 8 लाख से अधिक बूथों तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे 120 कार्यकर्ता जिस विचारधारा के लिए शहीद हुए हैं, उस विचारधारा को देश में व्यापक स्तर पर फैलाने का काम तेजी से आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री विजयन जी को कहना चाहता हूं कि विजयन जी, आप हिंसा का कीचड़ जितना उछालोगे, कमल उतना ही तेजी से खिलकर और निखर कर बाहर आयेगा। उन्होंने कहा कि केरल में हमारे 120 से अधिक कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया है, कई लोगों के घर जला दिए गए हैं। कई लोगों को अपाहिज कर दिया गया है, भाजपा एवं संघ के कार्यालय जलाए गए हैं, मैं आज केरल भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के सभी कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि केरल में हिंसा के खिलाफ

भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई अंत तक जारी रहेगी और भाजपा इसको जीत कर ही दम लेगी।

श्री शाह ने कहा कि हिंसा का रास्ता हमारा रास्ता नहीं है, जनजागृति और जनता को जोड़ना हमारा रास्ता है, हम इसी रास्ते के पथिक हैं और इस पथ पर डटे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी विचारधारा के आधार में केरल की जनता में जागृति लायें, देश भर में जनजागृति लायें, बुद्धिजीवियों को जगाएं और इस कम्युनिस्ट हिंसा के खिलाफ सब को एकजुट करें। उन्होंने कहा कि केरल में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएं, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ■

'विकास क्रांति के गौरव को जन-जन तक पहुंचाना है'

'हूं विकास छू, हूं गुजरात छू' के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक गुजरात गौरव यात्रा निकाल रही है। इस दौरान कुल 138 जनसभाओं को संबोधित किया जाएगा। यह यात्रा राज्य में 4 हजार 657 कि.मी. की यात्रा तय कर गांधीनगर पहुंचेगी। यात्रा के दो मार्ग होंगे। इनमें से एक मार्ग का नेतृत्व गुजरात के उप मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल करेंगे, जबकि दूसरे मार्ग का नेतृत्व गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री जीतू वघानी करेंगे। गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत 1 अक्टूबर को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर की। यात्रा के दौरान कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रैलियों में भाग लेंगे। इस यात्रा का समापन अहमदाबाद में होगा, जहां समापन समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह उपस्थित रहेंगे।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 1 अक्टूबर को लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन भूमि करमसद (गुजरात) से गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत की और इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से गुजरात की विकास यात्रा को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इसके पूर्व श्री शाह ने करमसद में भारत की एकता एवं अखंडता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के घर जाकर उनका वंदन किया और श्रद्धा-सुमन अर्पित किया। इसके बाद उन्होंने करमसद में भारत माता के वीर सपूत एवं राष्ट्र गौरव सरदार पटेल की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित की।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हम गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत सरदार पटेल की उस पावन भूमि से कर रहे हैं, जहां से उन्होंने किसानों की आवाज बुलंद की थी, देश को एक करने का बीड़ा उठाया था और देश की एकता एवं अखंडता की नींव रखी थी। उन्होंने कहा कि गुजरात गौरव यात्रा आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से विजयी बनायेगी। उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी ने भ्रष्टाचार-मुक्त एवं निर्णायक सरकार और गुजरात विकास मॉडल को देश के सामने रखा था और तब देश की जनता को यह मालूम पड़ा कि एक लोक-कल्याणकारी सरकार किस तरह से काम करती है और विकास को कैसे जन-जन तक पहुंचाती है।

राहुल गांधी पर करारा प्रहार करते हुए श्री शाह ने कहा कि राहुल गांधी गुजरात आकर भारतीय जनता पार्टी के शासन काल का हिसाब मांगते हैं, लेकिन तीन पीढ़ियों तक कांग्रेस पार्टी ने जो अन्याय गुजरात के साथ किया है, पहले इसका जवाब राहुल गांधी गुजरात की जनता को दें। उन्होंने कहा कि देश की आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने गुजरात के साथ अन्याय करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सरदार पटेल के साथ अन्याय किया, जब तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, सरदार पटेल को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। कांग्रेस ने संसद में सरदार पटेल का तैल चित्र तक नहीं लगने दिया, उनके लिए आयोजित श्रद्धांजलि सभा में रुकावट डाली गई, गुजरात की जनता कांग्रेस से सरदार पटेल के अपमान पर जवाब मांग रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पहली पीढ़ी ने सरदाल वल्लभ भाई पटेल के साथ अन्याय किया। कांग्रेस की दूसरी पीढ़ी ने देश के छठे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भाई के साथ अन्याय किया और कांग्रेस की तीसरी पीढ़ी ने भारत के विकास पुरुष प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ अन्याय किया, कांग्रेस

को इसका जवाब देना होगा।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मैं आजादी से लेकर 1995 तक के कांग्रेस के शासन और 1995 से 2017 तक के भारतीय जनता पार्टी के शासन का हिसाब-किताब लेकर गुजरात की जनता के सामने उपस्थित हुआ हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में गुजरात अंधेरे में जीने को विवश था, जबकि भाजपा के समय गुजरात में 24 घंटे बिजली आ रही है। कांग्रेस के समय शिक्षा के प्रति उदासीनता थी जबकि भाजपा के समय समृद्ध शिक्षण नीति है, कांग्रेस की सरकार में गुजरात में सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी, आज गुजरात में रोड सहित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम हुई है। उन्होंने कहा कि गुजरात की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार की प्रतीक थी, जबकि भाजपा सरकार पारदर्शिता और विकास की प्रतीक है। श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के गुजरात शासन की तुलना करने पर पता चलता है कि चाहे वह बजट हो, कैपिटल इनकम हो, बिजली का उत्पादन हो, इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, एग्रीकल्चर हो, दुग्ध उत्पादन हो - हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की तुलना में कई गुना अधिक विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि 1995 से पहले कांग्रेस शासन में और 1995 के बाद आज तक भाजपा शासन में गुजरात के विकास में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले केवल दक्षिणी और उत्तरी गुजरात में ही डेयरी उद्योग विकसित था, मोदी जी ने इसे सौराष्ट्र से लेकर कच्छ तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि पहले राज्य की सहकारी संस्थाएं किसानों को 14% ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराती थी, आज केवल 1% पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले गुजरात पानी के संकट से लगातार जूझ रहा था, लेकिन श्री नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में चेक डैम और विभिन्न सहकारी आयामों के माध्यम से हमने तालाब, सुजलाम सुफलाम और नर्मदा योजना के तहत पानी को जन-सुलभ बनाने के साथ-साथ राज्य के हर खेत तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने कहा कि 1995 से पहले और आज के गुजरात में कृषि उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि 1995-96 में जहां राज्य में केवल 47 लाख मीट्रिक टन अनाज का उत्पादन होता था वहीं 2017 में उत्पादन बढ़ कर 63 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया है, इसी तरह 1995 में फलों का उत्पादन जहां केवल 21 लाख मीट्रिक टन हुआ करता था, आज वह लगभग 86 लाख मीट्रिक टन हो गया है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हमने श्री नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में गुजरात में विकास की नई कहानी लिखी है। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू-मुक्त गुजरात बनाने का काम श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने किया है। उन्होंने कहा कि वाईब्रैंट गुजरात के माध्यम से राज्य में उद्योग और इन्वेस्टमेंट लाने का काम श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि चाहे साक्षरता दर हो, बिजली उत्पादन व उपभोग के आंकड़े हों, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो या फिर वाहनों की संख्या में इजाफा - हर क्षेत्र में श्री नरेन्द्र मोदी की अगुआई में गुजरात ने विकास की एक नई मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि गुजरात में भाजपा शासनकाल में इंजीनियरिंग सीटों में 14 गुनी और मेडिकल सीटों में 7 गुने की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के शासन में यूनिवर्सिटीज की संख्या भी लगभग दोगुनी हुई है। उन्होंने कहा कि गुजरात में 1995-96 में प्रति व्यक्ति आय महज 13,665 रुपये थी, जो 2017 में आज बढ़कर 1,43,504 रुपये तक पहुंच गई है जो कि राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। कांग्रेस पर प्रहार जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को विकास के आंकड़े दिखते नहीं और वह गुजरात के विकास का मजाक उड़ा रही है। आगामी विधान सभा चुनाव में गुजरात की जनता कांग्रेस को इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि 1995 से लेकर 2017 तक कई क्षेत्रों में गुजरात प्रथम स्थान पर रहा है, इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेन्द्र भाई मोदी को जाता है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार ने गुजरात के साथ हमेशा अन्याय किया है चाहे रेवेन्यू शेयरिंग की बात हो, हाईवे बनाने की बात हो, नर्मदा योजना की बात या फिर सरदार पटेल के साथ अन्याय हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में 13वें वित्त आयोग में गुजरात की शेयर इन सेन्ट्रल टैक्स में हिस्सेदारी 43,345 करोड़ थी, जबकि 14वें वित्त आयोग में मोदी सरकार ने गुजरात के लिए शेयर इन सेन्ट्रल टैक्स के रूप में 1,22,453 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। उन्होंने कहा कि ग्रांट इन ऐड को 84,86 करोड़

रुपये से बढ़ा कर 17,962 करोड़ और डिजास्टर रिलीफ को 2,081 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,920 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोकल बॉडीज ग्रांट के लिए कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 13वें वित्त आयोग में गुजरात को 2,723 करोड़ रुपये दिए जाते थे, जबकि मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग में गुजरात को इस क्षेत्र में 15,042 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर जब केंद्र में कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, तब गुजरात को विकास के लिए केवल 63,346 करोड़ रुपए मिलते थे, आज जब केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब गुजरात को 1,58,377 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू हो, हाइवे हो या नर्मदा योजना, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के लिए काफी काम किया है। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 56 साल पहले 1961 में सरदार सरोवर बांध की आधारशिला रखी थी, लेकिन उसे पूरा करने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया जिससे गुजरात के हर खेत तक पानी पहुंच पायेगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इसका जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस ने नर्मदा योजना को अवरुद्ध करने का पाप क्यों किया? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुजरात को न्याय, अधिकार और गौरव के साथ विकास दिया है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में गुजरात का गौरवपूर्ण और शांतिपूर्ण विकास हुआ है। 1995 से पहले के गुजरात और 1995 के बाद से लेकर आज तक के गुजरात में प्रदेश के विकास की गौरवगाथा समाई हुई है और यह पहले मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी के कारण ही संभव हो पाया है।

श्री शाह ने कहा कि श्री नरेन्द्र भाई मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं और गुजरात में विजय भाई रूपाणी और नितिन भाई पटेल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है, अब गुजरात का विकास डबल इंजन की गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वे गुजरात गौरव यात्रा के माध्यम से श्री नरेन्द्र भाई मोदी की अगुआई में गुजरात की विकास यात्रा के आंकड़ों को राज्य के गांव-गांव और जन-जन तक पहुंचाने का प्रण लें और 150 से अधिक सीटें जीतकर राज्य में एक बार फिर से विकासोन्मुखी एवं लोक-कल्याणकारी भाजपा की सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध हो जाएं। ■

'भाजपा सरकार आई तो राज्य से गुंडागर्दी और कांग्रेस दोनों का सफाया हुआ'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को पोरबंदर, गुजरात से गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत की और गुजरात के विकास में अवरोध उत्पन्न करने के लिए कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। पोरबंदर से शुरू हुए इस गौरव यात्रा का नेतृत्व गुजरात भाजपा के अध्यक्ष श्री जीतूभाई वाघाणी कर रहे हैं। ज्ञात हो कि 01 अक्टूबर को करमसद से गुजरात के उप-मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल के नेतृत्व में पहले गुजरात यात्रा का शुभारंभ हुआ। इससे पहले श्री शाह पोरबंदर स्थित महात्मा गांधी की पावन जन्मभूमि कीर्ति मंदिर गए और बापू को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के जोश और उत्साह से यह निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 150 से अभी अधिक सीटें जीत कर फिर से गुजरात मे सरकार बनायेगी।

कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए श्री शाह ने कहा कि हमें पोरबंदर का विकास करने का गौरव है, जबकि कांग्रेस ने पोरबंदर के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि गुजरात की विकास यात्रा को तीन पड़ावों में विभक्त किया जा सकता है - पहला देश की आजादी से लेकर गुजरात की स्थापना तक का कालखंड, दूसरा गुजरात की स्थापना से लेकर 1995 तक के कांग्रेस शासन का कालखंड और तीसरा 1995 से भाजपा शासन में शुरू हुई गुजरात की विकास यात्रा का कालखंड। उन्होंने कहा कि 1995 में शुरू हुई गुजरात के समग्र विकास की यात्रा श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के शासन में उस ऊंचाई पर पहुंची है कि लोग आज गुजरात के विकास का उदाहरण देते हैं, इससे बढ़कर गौरव की बात क्या हो सकती है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गुजरात को कौमी दंगे दिए थे, कांग्रेस के शासनकाल में गुजरात में सर्वत्र अराजकता और गुंडागर्दी का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में जो भी आम जनता को प्रताड़ित करते थे, उन सभी असामाजिक तत्त्वों को जेल में डालने का काम गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि जब हम गुजरात में विपक्ष में थे तब भी हमने गुंडागर्दी के विरोध में संघर्ष समिति बनाई थी और जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो गुजरात से गुंडागर्दी और कांग्रेस दोनों का सफाया हुआ, दोनों की हार हुई। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू-मुक्त गुजरात बनाने का हमें गौरव है। ■

जीएसटी: छोटे, सर्राफा कारोबारियों, किसानों और आम लोगों को बड़ी राहत

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने 6 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित अपनी 22वीं बैठक में छोटे, मझोले कारोबारियों, किसानों और आम लोगों को बड़ी राहत देने का निर्णय किया और निम्नलिखित सुगम या सुविधाजनक परिवर्तनों की सिफारिश की है:

कंपोजीशन स्कीम

- कंपोजीशन स्कीम अब से उन करदाताओं को भी उपलब्ध कराई जाएगी जिनका कुल वार्षिक कारोबार 1 करोड़ रुपये तक है, जबकि इसके तहत मौजूदा टर्नओवर सीमा 75 लाख रुपये है। जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड को छोड़ विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए कारोबार की यह सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये की जाएगी। वहीं, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के लिए कारोबार सीमा एक करोड़ रुपये होगी। बढ़ी हुई सीमा के तहत कंपोजीशन स्कीम से लाभ उठाने की सुविधा यह कर प्रणाली अपना चुके करदाताओं के साथ-साथ नए करदाताओं को भी 31 मार्च, 2018 तक उपलब्ध होगी। जिस भी महीने में कंपोजीशन स्कीम से लाभ उठाने का विकल्प अपनाया जाएगा, उसके ठीक अगले महीने की पहली तारीख से ही यह विकल्प परिचालन में आ जाएगा। इस योजना के नए प्रवेशकों को केवल उस तिमाही की शेष अवधि के लिए फॉर्म 'जीएसटीआर-4' में रिटर्न दाखिल करना होगा, जब से यह स्कीम अमल में आएगी। ये नए प्रवेशक पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए सामान्य करदाता के रूप में रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। कारोबार सीमा में वृद्धि से अब और ज्यादा बड़ी संख्या में करदाताओं के लिए यह संभव होगा कि वे कंपोजीशन स्कीम के तहत आसान अनुपालन से लाभ उठा सकें। इससे एमएसएमई सेक्टर के काफी लाभान्वित होने की आशा है।
- ऐसे व्यक्ति जो वैसे तो कंपोजीशन स्कीम से लाभ उठाने के पात्र हैं, लेकिन कोई छूट प्राप्त सेवा प्रदान कर रहे हैं (जैसे कि बैंकों में धनराशि जमा कर रहे हैं और उस पर ब्याज प्राप्त कर रहे हैं), उन्हें इस स्कीम के लिए पहले अयोग्य माना जाता था। अब यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो वैसे तो कंपोजीशन स्कीम से लाभ उठाने के पात्र हैं और कोई छूट प्राप्त सेवा प्रदान कर रहे हैं, वे कंपोजीशन स्कीम के लिए उपयुक्त पात्र होंगे।
- कंपोजीशन स्कीम को और अधिक आकर्षक बनाने वाले उपायों पर गौर करने के लिए एक मंत्री समूह (जीओएम) गठित किया जाएगा।

लघु एवं मझोले उद्यमों को राहत

- वर्तमान में, अंतर-राज्य जॉब वर्कर को छोड़कर अंतर-राज्य कर योग्य आपूर्ति करने वाले किसी भी उद्यम के लिए पंजीकृत होना आवश्यक है, भले ही उसका टर्नओवर (कारोबार) कितना भी क्यों न हो। अब उन सेवा प्रदाताओं को पंजीकरण कराने से छूट देने का निर्णय लिया गया है जिनका कुल वार्षिक कारोबार 20 लाख (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर विशेष श्रेणी के राज्यों में 10 लाख रुपये) रुपये से कम है, भले ही वे सेवाओं की अंतर-राज्य कर योग्य आपूर्ति क्यों न कर रहे हों। इस कदम से छोटे सेवा प्रदाताओं की अनुपालन लागत काफी कम हो जाने की उम्मीद है।
- 1.5 करोड़ रुपये तक के कुल वार्षिक कारोबार वाले छोटे एवं मझोले कारोबारियों के लिए भुगतान में आसानी और रिटर्न भरने में सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि इस तरह के करदाताओं को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही अर्थात अक्टूबर-दिसंबर, 2017 से फॉर्म जीएसटीआर-1, 2 और 3 में तिमाही रिटर्न दाखिल करने होंगे और केवल तिमाही आधार पर ही कर अदा करना होगा। इस तरह के छोटे करदाताओं के पंजीकृत खरीदार मासिक आधार पर यानी हर माह आईटीसी का लाभ लेने के पात्र होंगे। इस तरह के करदाताओं के लिए तिमाही रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथियां उचित समय पर घोषित

जीएसटी फैसलों से देशवासियों की दिवाली जल्दी आ गई: नरेंद्र मोदी

छोटे व मध्यम व्यापारों के लिए जीएसटी में किए गए व्यापक बदलावों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन फैसलों से देशवासियों की दिवाली जल्दी आ गई है। इसमें बदलाव कर सिंपल टैक्स को और सिंपल कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार नहीं चाहती कि व्यापारी वर्ग लाल फीताशाही में फंसे।

की जाएंगी। इस बीच, सभी करदाताओं के लिए दिसंबर, 2017 तक मासिक आधार पर फॉर्म जीएसटीआर-3बी दाखिल करना आवश्यक होगा। सभी करदाताओं के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर, 2017 हेतु फॉर्म जीएसटीआर-1, 2 और 3 दाखिल करना भी आवश्यक है। जुलाई, 2017 के लिए रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथियां पहले ही घोषित की जा चुकी हैं। इस संबंध में अगस्त और सितंबर, 2017 के लिए नियत तिथियां उचित समय पर घोषित की जाएंगी।

- सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उप-धारा (4) के तहत और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उप-धारा (4) के तहत रिवर्स चार्ज व्यवस्था 31 मार्च, 2018 तक लागू नहीं की जाएगी और विशेषज्ञों की एक समिति इसकी समीक्षा करेगी। इससे छोटे कारोबारियों को फायदा होगा और उनकी अनुपालन लागत काफी घट जाएगी।
- प्राप्त अग्रिमों पर जीएसटी का भुगतान करने की आवश्यकता भी छोटे डीलरों और निर्माताओं के लिए परेशानी भरी साबित हो रही है। इस तरह के मामलों में उनकी असुविधा कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि 1.5 करोड़ रुपये तक के कुल वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए प्राप्त अग्रिम पर उस समय जीएसटी अदा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह की आपूर्ति पर जीएसटी केवल तभी देय होगा, जब संबंधित माल की आपूर्ति कर दी जाएगी।
- इस आशय की जानकारी मिली है कि माल परिवहन एजेंसियां (जीटीए) अपंजीकृत व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस वजह से छोटे अपंजीकृत कारोबारियों को हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए किसी भी जीटीए द्वारा अपंजीकृत व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को जीएसटी से छूट दी जाएगी।

अन्य सुविधाजनक उपाय

- व्यापार एवं उद्योग जगत और सरकारी विभागों की तैयारी का आकलन करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि पंजीकरण के साथ-साथ टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों पर अमल को 31 मार्च 2018 तक स्थगित रखा जाएगा।
- ई-वे बिल प्रणाली को 1 जनवरी, 2018 से क्रमबद्ध ढंग से लागू किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2018 से इसे देश भर में लागू कर दिया जाएगा। व्यापार और उद्योग जगत को जीएसटी व्यवस्था के अनुरूप खुद को ढालने हेतु और अधिक समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
- जुलाई-सितंबर, 2017 की तिमाही के लिए कंपोजीशन स्कीम के तहत किसी भी करदाता द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-4 में रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 नवंबर, 2017 कर दी जाएगी। इसके साथ ही जुलाई, अगस्त और सितंबर 2017 के लिए किसी भी इनपुट सेवा वितरक द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-6 में रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 नवंबर, 2017 कर दी जाएगी।
- पंजीकृत व्यक्तियों के कुछ विशेष वर्गों को राहत प्रदान करने के लिए चालान (इनवॉयस) नियमों को संशोधित किया जा रहा है। ■

पेट्रोल और डीजल पर बेसिक उत्पाद शुल्क 2 रुपये प्रति लीटर कम

भारत सरकार ने 4 अक्तूबर, 2017 से पेट्रोल और डीजल (ब्रांडेड और गैर-ब्रांडेड दोनों) पर बेसिक उत्पाद शुल्क 2 रुपये प्रति लीटर कम करने का फैसला किया है। सरकार ने यह फैसला कच्चे पेट्रोलियम तेल तथा पेट्रोल और डीजल के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के प्रभाव को कम करने और आम आदमी के हितों की रक्षा के लिए पेट्रोल और डीजल के बढ़ते खुदरा बिक्री मूल्य को कम करने के लिए किया है। उत्पाद शुल्क में इस कटौती से पूरे एक वर्ष में 26,000 करोड़ रुपये का और वर्तमान वित्त वर्ष के शेष हिस्से के दौरान करीब 13,000 करोड़ रुपये का घाटा होगा। इससे पहले पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि के कारण दिल्ली में पेट्रोल और डीजल का खुदरा बिक्री मूल्य 02 अक्तूबर 2017 को बढ़कर क्रमशः 70.83 रुपये प्रति लीटर और 59.07 रुपये प्रति लीटर हो गया। पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में यह वृद्धि थोक मूल्य सूचकांक मंहगाई में दिखाई देने लगी थी, जो अगस्त, 2017 में बढ़कर 3.24 प्रतिशत हो गई, जबकि जुलाई, 2017 में यह 1.88 प्रतिशत थी। इसके कारण सरकार को इस संबंध में तेजी से फैसला लेना पड़ा।

देश में 6.26 करोड़ करदाता

3.7 लाख करोड़ रुपये हुआ प्रत्यक्ष कर राजस्व संग्रह

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने 29 सितम्बर को कहा कि वित्त मंत्रालय के आयकर विभाग ने कर प्रशासन में दक्षता, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पिछले दो-तीन वर्षों में अनेक कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री ने इन पहलों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 50 लाख रुपये तक की आमदनी वाले करदाताओं के लिए सिर्फ एक पेज वाला आईटीआर-1 (सहज) फॉर्म पेश किया गया।

विमुद्रीकरण के असर और आयकर विभाग के विभिन्न सक्रिय कदमों पर प्रकाश डालते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष करों के मामले में राजस्व संग्रह वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 14.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 8,49, 818 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि चालू वित्त वर्ष में 18 सितंबर, 2017 तक प्रत्यक्ष करों का शुद्ध संग्रह 15.7 प्रतिशत बढ़कर 3.7 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि करदाताओं की कुल संख्या वित्त वर्ष 2012-13 के 4.72 करोड़ से काफी बढ़कर वित्त वर्ष 2016-17 में 6.26 करोड़ हो गई।

वित्त मंत्री ने कहा कि 2.5 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की आमदनी वाले करदाताओं के लिए टैक्स दर 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई, जो दुनिया की न्यूनतम कर दरों में से एक है। वित्त मंत्री श्री जेटली ने यह भी कहा कि 5 लाख रुपये तक की आमदनी वाले ऐसे गैर-बिजनेस करदाताओं के लिए 'कोई जांच नहीं' अवधारणा शुरू की गई, जिन्होंने पहली बार टैक्स रिटर्न भरा था। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि ज्यादा से ज्यादा लोग कर दायरे में आएं, अपने-अपने आईटी रिटर्न भरें और निर्धारित टैक्स भरें। वित्त मंत्री 29 सितम्बर को 'आईटी विभाग की पहलों' विषय पर वित्त मंत्रालय से संबंद्ध सलाहकार समिति की दूसरी बैठक को संबोधित कर रहे थे।

प्रत्यक्ष करों के मामले में राजस्व संग्रह वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 14.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 8,49, 818 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि चालू वित्त वर्ष में 18 सितंबर, 2017 तक प्रत्यक्ष करों का शुद्ध संग्रह 15.7 प्रतिशत बढ़कर 3.7 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

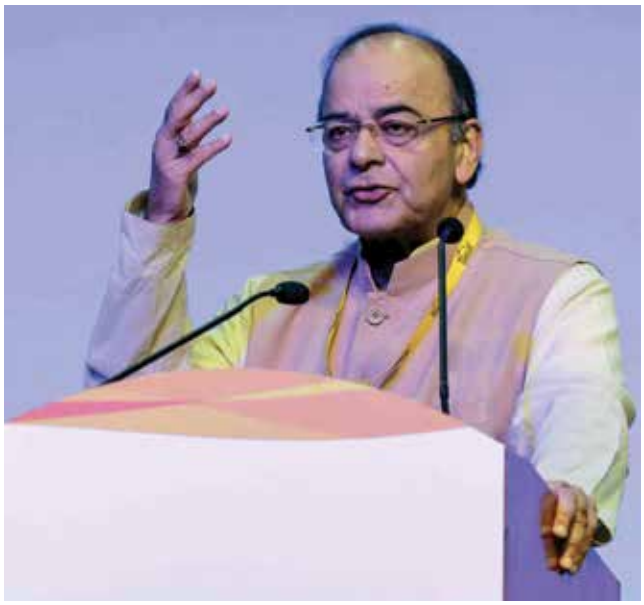

आयकर विभाग की अन्य पहलों पर प्रकाश डालते हुए वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि 50 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर घटाकर 25 प्रतिशत के स्तर पर ला दी गई, जिससे लगभग 96 फीसदी कंपनियों को कवर कर लिया गया। 01 मार्च, 2016 को अथवा उसके बाद गठित नई विनिर्माण कंपनियों को बगैर किसी छूट के 25 फीसदी की दर से टैक्स लगाए जाने का विकल्प दिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रक्रियागत सुधारों के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) से संबंधित क्रेडिट को 10 वर्षों के बजाय 15 वर्षों तक आगे ले जाने (कैरी फॉरवर्ड) की अनुमति दी गई।

जहां तक काले धन के खिलाफ छेड़े गए अभियान का सवाल है, आयकर विभाग ने वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद अनेक तरह के कदम उठाए हैं। इस संबंध में वित्त मंत्री ने काला धन अधिनियम 2015, बेनामी अधिनियम 1988 में किए गए व्यापक संशोधनों और ऑपरेशन क्लीन मनी इत्यादि का उल्लेख किया। वित्त मंत्री ने कहा कि 9 नवंबर, 2016 से लेकर 10 जनवरी, 2017 तक के विमुद्रीकरण संबंधी आंकड़ों के गहन अध्ययन के बाद लगभग 1100 तलाशियां ली गईं और इसके परिणामस्वरूप 513 करोड़ रुपये की नकदी सहित 610 करोड़ रुपये की राशि जब्त की गई। उन्होंने कहा कि 5400 करोड़ रुपये की अघोषित आय के बारे में पता लगा और

समुचित कार्रवाई के लिए लगभग 400 मामले ईडी और सीबीआई को सौंपे गए हैं।

'लेस कैश' अर्थव्यवस्था और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर विभाग ने अनेक कदम उठाए जिनमें 2 लाख रुपये अथवा उससे ज्यादा की नकदी की प्राप्ति पर जुर्माना लगाना, धर्मार्थ ट्रस्टों को नकद दान की सीमा को 10,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये करना और राजनीतिक दलों को 2000 रुपये या इससे अधिक का नकद दान नहीं किया जाना, इत्यादि शामिल हैं।

ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में विभाग की पहलों पर रोशनी डालते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल 97 फीसदी आयकर रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक ढंग से दाखिल किए गए, जिनमें से 92 फीसदी रिटर्न की प्रोसेसिंग 60 दिनों के भीतर कर दी गई और 90 फीसदी रिफंड 60 दिनों के भीतर जारी कर दिए गए। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि आयकर विभाग ने शिकायत निवारण प्रणाली 'ई-निवारण' शुरू की है, जिसके तहत ऑनलाइन एवं कागज पर लिखकर दी गई सभी शिकायतों को एकीकृत कर दिया गया है और इनका निवारण होने तक इन पर करीबी नजर रखी जाती है। प्रत्येक शिकायत को स्वीकार किया जाता है और उसके समाधान के बारे में सूचना ईमेल और एसएमएस के जरिये दी जाती है। वित्त मंत्री ने कहा कि 4.65 लाख ई-निवारण शिकायतों में से 84 फीसदी शिकायतों का निपटारा अब तक किया जा चुका है।

वित्त मंत्री श्री जेटली ने कहा कि 'ई-सहयोग' के जरिये सूचनाओं में अंतर वाले सभी मामलों को गैर-दखल तरीके से निपटाया जाता है, जिससे कि पूर्ण जांच को टाला जा सके। वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर विभाग द्वारा हर तिमाही लगभग 1.9 करोड़ वेतनभोगी करदाताओं को यह सूचना दी जाती है कि उनके नियोक्ताओं द्वारा कितना टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) जमा कराया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि विभाग की इन सभी ई-गवर्नेंस पहलों से कर निर्धारण अधिकारियों और करदाताओं के बीच प्रत्यक्ष संपर्क न्यूनतम हो गया है, जिससे करदाताओं का उत्पीड़न कम करने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और समय की बचत करने में मदद मिली है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कारोबार में सुगमता और वित्तीय बाजारों को बढ़ावा देने के लिए आयकर विभाग द्वारा उठाए गए कदमों पर भी प्रकाश डाला। इस संबंध में उन्होंने 50 लाख रुपये तक की आमदनी वाले प्रोफेशनलों के लिए प्रकल्पित कराधान योजना शुरू किए जाने का उल्लेख विशेष रूप से किया। इसी तरह कारोबारी आमदनी हेतु प्रकल्पित कराधान योजना के लिए सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में अवस्थित कंपनियों को लाभांश वितरण कर से मुक्त कर दिया गया है और उन्हें केवल 9 फीसदी की दर से मैट अदा करना होगा। ■

भारत में शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी

भारत में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। हाल ही में जारी एसआरएस बुलेटिन के मुताबिक वर्ष 2016 में भारत के आईएमआर में तीन अंकों (8 प्रतिशत) की गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2015 में जन्मे 1000 बच्चों में से 37 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। यह आंकड़ा वर्ष 2016 में घटकर 34 के स्तर पर आ गया है। इससे पिछले वर्ष भारत के आईएमआर में दो अंकों की गिरावट दर्ज की गई थी। भारत में जन्मे कुल बच्चों की संख्या में भी उल्लेखनीय कमी देखने को मिली है, जो पहली बार घटकर 25 मिलियन के स्तर से नीचे आई है। वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2016 के दौरान भारत में 90,000 कम नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई। वर्ष 2015 में 9.3 लाख नवजात शिशुओं की मृत्यु होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2016 में 8.4 लाख नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई थी।

एसआरएस बुलेटिन के मुताबिक नवजात बच्चे एवं बच्चियों की संख्या में अंतर निरंतर घटता जा रहा है। नवजात बच्चियों एवं बच्चों की मृत्यु दर में अंतर घटकर अब 10 फीसदी से भी कम रह गया है। इससे सरकार की 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना को काफी बढ़ावा मिला है।

उपर्युक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि मंत्रालय की रणनीतिक अवधारणा के सकारात्मक नतीजे अब आने शुरू हो गए हैं और इसके साथ ही इस मामले में खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयास भी अब सार्थक साबित हो रहे हैं। जहां तक सशक्त क्रियाशील समूह (ईएजी) वाले राज्यों का सवाल है, उत्तराखंड को छोड़ सभी राज्यों के आईएमआर में वर्ष 2015 की तुलना में कमी दर्ज की गई है। यह

कमी बिहार में 4 अंकों, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में 3-3 अंकों और छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं राजस्थान में 2-2 अंकों की रही है। सरकार की विभिन्न पहलों के जरिये स्वास्थ्य सेवा कवरेज बढ़ाने के देशव्यापी प्रयासों के परिणामस्वरूप भी सिर्फ एक साल में ही ये उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई हैं। सेवा प्रदान करने की व्यवस्था को मजबूत करना, गुणवत्ता का आश्वासन, आरएमएनसीएच+ए, मानव संसाधन एवं समुदाय संबंधी प्रक्रियाएं, सूचना एवं ज्ञान, दवाओं एवं निदान और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन इत्यादि भी इनमें शामिल हैं। ■

मनुष्य या मशीन

दीनदयाल उपाध्याय

मनुष्य ने मशीन को अपनी सहायता और सुविधा के लिए बनाया, किंतु आज वह उसका गुलाम बन गया है। फिर भी वह नई-नई मशीनें बनाता जाता है, इसी आशा में कि हर नई मशीन उसे नई और अधिक शक्ति प्रदान करेगी। आज सारा संसार इसी होड़ में लगा है और नई-नई उलझनें पैदा करता जा रहा है। चाहे हम साम्यवाद को लें या पूंजीवाद को, दोनों की समस्याएं मशीन युग की देन हैं। मशीनों ने शक्ति के केंद्रीकरण में सहायता दी है और वह ही सब समस्याओं की जड़ में है।

भारत गुलामी के अभिशाप के कारण ही क्यों न हो, मशीनों की इस दौड़ में काफ़ी पिछड़ गया है। अंग्रेज़ी राज्य के मातहत हम अंग्रेजों की विकसित मशीनों से प्राप्त शक्ति के द्वारा शोषित ही रहे। मशीनों को खाने के लिए कच्चा माल देना तथा उनसे बनी हुई वस्तुओं के लिए बाजार जुटाना मात्र हमारा काम रहा। अब जब अंग्रेज चले गए हैं तथा हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं, हमारे मन में भी मशीनों की दौड़ में हिस्सा लेने की स्वाभाविक इच्छा उत्पन्न होती है। जिस शक्ति के सहारे अंग्रेज हमें गुलाम बनाकर रख सके, यदि वह हमें भी प्राप्त हो जाए तो हम दृढ़ हो सकेंगे, यह सीधा सा तर्क हमारे समक्ष है। किंतु हमें गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए और पिछले डेढ़ सौ वर्ष के अभिशाप को वरदान में बदलना चाहिए।

मशीन से अधिक उत्पादन की शक्ति प्राप्त होती है। साधारणतया अधिक उत्पादन समृद्धि का लक्षण माना जाता है, किंतु यह सर्वांगपूर्ण विचार नहीं। उत्पादन अपने में ही हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता। उत्पादन तो उपभोग के लिए चाहिए। अतः यदि उत्पाद वस्तु उपभोग्य या उपयुक्त नहीं हुई तो उसका अवमूल्यन हो जाएगा तथा वह समृद्धि का द्योतक नहीं होगा।

मनुष्य अधिकाधिक उपभोग तो करना चाहता है, किंतु उसकी उपभोग-सामर्थ्य असीम नहीं है। वह अमर्यादित रूप में नहीं बढ़ सकती, यद्यपि यह सत्य है कि आज अधिकांश व्यक्तियों की इस सामर्थ्य में पर्याप्त वृद्धि की गुंजाइश है। (यहां हम इसका विचार नहीं करेंगे कि इस वृद्धि से कहां तक वास्तविक सुख एवं आनंद की उपलब्धि संभव है) किंतु यह सामर्थ्य एकाएक नहीं बढ़ सकती। सामाजिक रीति-रिवाज, व्यवस्था एवं जीवन के मूल्यों के साथ-साथ मनुष्य की क्रयशक्ति भी उसकी सामर्थ्य का निर्णय करती है।

आज भारत के जन-साधारण की क्रयशक्ति बढ़ाना ही हमारा प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। उसके लिए प्रथम आवश्यकता है, प्रत्येक को काम मिलता रहे। बेकारी क्रयशक्ति को बिलकुल समाप्त कर देती है। भारत के हर व्यक्ति को काम मिले, उसके लिए नए उद्योग-धंधे प्रारंभ करने होंगे, किंतु वे ऐसे होने चाहिए कि उनके बने हुए माल को बाजार मिल सके तथा वहां किसी चलते हुए उद्योग को बंद करके बेकारी और न बढ़ा दे। बाजार देश और विदेश दोनों ही स्थानों पर मिल सकते हैं। किंतु विदेश के स्थान पर हमें देश के बाजार की ओर पहले ध्यान देना होगा, कारण-विदेशों के बाजार में दूसरे देश हमसे बहुत पहले पहुंच चुके हैं। उन्हें हटाना सहज नहीं, वरन् बाजारों को अपने पास रखने के लिए दुनिया के देश जिस युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, हमें भी उसमें साथ देना होगा। उस हालत में हमारा ध्यान युद्ध सामग्री को इकट्ठा करने की ओर जाएगा, जो विकास के स्थान पर विनाश के लिए उत्तरदायी होगा।

देश का बाज़ार दो प्रकार से प्राप्त होगा। प्रथम बाहर से आने वाले माल पर प्रतिबंध लगाकर स्वदेशी का आश्रय ग्रहण करने से, दूसरे जन-साधारण की क्रयशक्ति को बढ़ाने से जो कि धन के समांतर वितरण एवं विकेंद्रीकरण से हो सकेगा।

जब मशीन मनुष्य को हटाकर उसका स्थान ले लेती है, तब क्रयशक्ति क्षीण होने लगती है। फलतः उत्पादित वस्तु की मांग कम होने से उसका मूल्य गिर जाता है। मजदूरों को हटाने से यद्यपि खर्चा कुछ कम हो जाता है किंतु ऊपर का खर्चा (Establishment and Management) तो कम होता नहीं, यहां तक कि वह अनुपात में बढ़ ही जाता है और इस प्रकार उद्योग को कोई बड़ा लाभ नहीं होता, जब तक कि वह नया बाज़ार न ढूंढ ले। यह तभी संभव है जबकि या तो विदेशों में बाज़ार मिल जाए या देश में दूसरे उद्योग-धंधों को हानि पहुंचाए। यद्यपि दूसरे उद्योग धंधों को हानि पहुंचाने पर वहां भी बेकारी बढ़ती है, जो क्रय शक्ति को और भी घटाने का कारण बनती है। अतः पश्चिम के अनेक देश अपने देश की समृद्धि विदेशों के बाजार पर ही टिकाते आए हैं। जहां तक भारत का संबंध है, वह विदेशी बाज़ारों के भरोसे अपना आर्थिक ढांचा खड़ा नहीं कर सकता। उसे तो अपने ही सहारे खड़ा होना होगा। अतः हम मशीनों को बिना सोचे-समझे स्वीकार नहीं कर सकते। बड़ी-बड़ी मशीनें हमारी प्रगति का नहीं अपितु परागति का लक्षण होंगी।

भारत की सबसे बड़ी पूंजी हमारी जनशक्ति है। हमें पहले उसका पूर्ण उपयोग करना होगा। गांवों में काम करने वाले खेतिहर मजदूरों

को ही वर्ष में औसतन 189 दिन काम मिलता है। शेष दिन उनकी शक्ति बेकार जाती है। हमें पहले उनकी शक्ति का उपयोग करना होगा। आज उनकी कुल आमदनी 447 रुपए प्रतिवर्ष है। हमें इसमें वृद्धि करनी होगी। क्या इनके लिए बड़ी-बड़ी मिलें खोली जाएं। उस हालत में इन्हें गांव से बाहर आना होगा तथा गांव में मजदूरों की समस्या हो जाएगी। फिर साढ़े तीन करोड़ लोगों को मिल में खपाने के लिए कितनी मशीनें चाहिए उनसे जो माल बनेगा, वह खपेगा कहां?

खेतिहर मजदूरों के अतिरिक्त भी हमारे यहां बेकारों की एक बड़ी संख्या है। शहरों में विभिन्न प्रकार काम करने वाले घरेलू नौकर, कुली, मजदूर आदि की भी क्रयशक्ति बहुत कम है। उसे भी हम बड़ी-बड़ी मिलों के द्वारा नहीं बढ़ा सकते। वैज्ञानिकता के कारण दिन-प्रतिदिन मजदूर बेकार होते जा रहे हैं। हम मशीन का पेट भरने के लिए मनुष्य को भूखा रख रहे हैं।

आज जो भी नए-नए उद्योग प्रारंभ होते हैं, वे पुराने छोटे उद्योगों को नष्ट करते जाते हैं। एक बाटा का कारखाना यद्यपि हजार-दो हजार लोगों को काम देता है, किंतु वह गांवों में हज़ारों की संख्या में जूते बनाने वालों को बेकार बना देता है। अंग्रेजी राज्य में मैनचेस्टर और लिवरपूल के कारखानों ने भारत के उद्योग-धंधों को चौपट किया था तथा हमें बेकार बनाया। आज अहमदाबाद और कानपुर में ही मैनचेस्टर हो गए हैं। सिवाय इसके कि वे हमारे पूंजीपतियों को तथा थोड़े से मजदूरों को लाभ पहुंचाते हैं, वे हमारे बुनियादी उद्योगों को चौपट करते जा रहे हैं।

अतः आवश्यकता है कि हम अपने गांवों में तथा क़स्बे में चलने वाले उद्योगों को अपना आधार बनाएं। उनका विकास एवं उनकी वृद्धि करने की कोशिश करें। उनके द्वारा हमारे बाजार की जो मांग पूरी होती है, उसके लिए न तो विदेशी और न देशी बड़े-बड़े उद्योगों को प्रतियोगी होने दें।

हमारी जिन आवश्यकताओं की पूर्ति इन छोटे-छोटे उद्योगों से नहीं हो सकती, उन्हें नए सिरे से गांवों और कस्बों में प्रारंभ करें, किंतु वह भी छोटे आधार पर। बड़े-बड़े उद्योग इन छोटे उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जैसे उत्पादक वस्तुओं के लिए ही चलाए जाएं। इस प्रकार सभी उपयोगी वस्तुएं छोटे और गृह उद्योगों द्वारा उत्पादक वस्तुएं बड़े उद्योगों द्वारा तैयार होंगी। वे एक-दूसरे के पूरक हो सकेंगे। इसमें भारत के हर व्यक्ति को काम मिल सकेगा। आर्थिक शक्ति के विकेंद्रीकरण के कारण जन-साधारण की क्रयशक्ति का स्तर ऊंचा होगा, जिससे ज्यों-ज्यों उत्पादन बढ़ता जाएगा, त्यों-त्यों उसकी मांग भी बढ़ती जाएगी।

संक्षेप में भारत की आर्थिक समस्या का हल यह है कि हम मनुष्य और मशीन की लड़ाई में मनुष्य को प्रमुखता दें। हम मशीन युग के पुजारी नहीं, मानव युग के ही पुजारी बने रहे। हां ज्यों-ज्यों मानव की शक्ति मशीन को काबू में रखने की बढ़ती जाएगी, त्यों-त्यों मशीन विकसित होती जाएगी। ■

— (पांचजन्य, अक्तूबर 25, 1954)

सेवाओं का एकीकरण मेरी प्राथमिकता: रक्षा मंत्री

रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 10 अक्टूबर को दिल्ली कैंट के मानकेशॉ सेंटर में आयोजित सेना कमांडर सम्मेलन में भाग लिया और सेना प्रमुख और सेना के कमांडरों सहित उच्चाधिकारियों को संबोधित किया। रक्षा मंत्री का स्वागत करते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद रक्षा मंत्री सियाचिन सहित कई फारवर्ड पोस्ट्स का दौरा कर चुकीं हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि रक्षा मंत्री उत्तर-पूर्व और तिब्बत के सीमा क्षेत्रों की भी यात्रा कर चुकीं हैं। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा क्षेत्रों की उनकी यात्रा आँखे खोल देने वाली थी। उन्होंने भारतीय सेना के पेशेवर दृष्टिकोण प्राथमिक आपदाओं के दौरान कार्यकुशलता और पूर्वोत्तर राज्य में विद्रोह पर नियंत्रण जैसे कार्यों की प्रशंसा की।

सेना के क्षमता विकास, रणनीतिक अवसंरचना विकास, सैन्य संशोधन, सेवारत व सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों व परिवार के कल्याण के प्रति मंत्री महोदया ने बारीकी से निगरानी का भरोसा दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि एचएडीआर उपकरणों के प्रावधान के लिए गृह मंत्री को प्रस्ताव भेजा है। भारतीय सेना प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उपरोक्त उपकरणों का इस्तेमाल कर सकेगी। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण, संचार, परिवहन और साइबर क्षेत्रों का एकीकरण उनकी प्राथमिकता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेनाओं का मनोबल सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने राजनयिक रक्षा सहयोग, 'मेक इन इंडिया' का समर्थन और राष्ट्र निर्माण के प्रति भारतीय सेना के योगदान की प्रशंसा की। ■

सरदार वल्लभ भाई पटेल

(31 अक्टूबर 1875 – 15 दिसंबर, 1950)

सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम सरदार पटेल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875, नाडियाड गुजरात में हुआ था। सरदार पटेल बैरिस्टर और राजनेता थे। भारत की आज़ादी के बाद पहले तीन वर्ष तक वह उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रहे। 1991 में उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' दिया गया। दृढ़ व्यक्तित्व के लिए 'राष्ट्रपिता' महात्मा गांधी ने उन्हें 'सरदार' और 'लौह पुरुष' की उपाधि दी।

जीवन-परिचय

सरदार पटेल का जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ था। सरदार पटेल ने करमसद में प्राथमिक विद्यालय और पेटलाद स्थित उच्च विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्होंने अधिकांश ज्ञान स्वाध्याय से अर्जित किया। वक़ालत के पेशे में तरक्की करने के लिए कृतसंकल्प पटेल ने मिड्ल टेंपल के अध्ययन करने के लिए अगस्त 1910 में लंदन की यात्रा की। वहां उन्होंने मनोयोग से अध्ययन किया और अंतिम परीक्षा में उच्च प्रतिष्ठा के साथ उत्तीर्ण हुए। 1917 से 1924 तक सरदार पटेल ने अहमदनगर के पहले भारतीय निगम आयुक्त के रूप में सेवा प्रदान की और 1924 से 1928 तक वह इसके निर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष रहे। 1928 में पटेल ने बढ़े हुए करों के ख़िलाफ़ बारदोली संघर्ष का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। बारदोली आन्दोलन

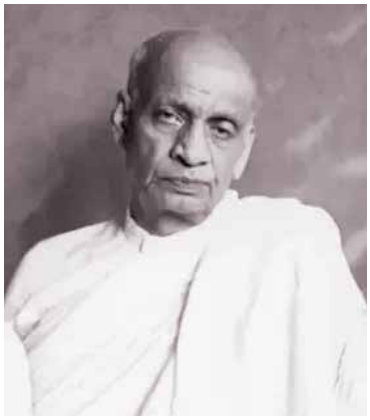

के कुशल नेतृत्व के कारण उन्हें 'सरदार' की उपाधि मिली और उसके बाद देश भर में राष्ट्रवादी नेता के रूप में उनकी पहचान बन गई। उन्हें व्यावहारिक, निर्णायक और यहां तक की कठोर भी माना जाता था तथा अंग्रेज़ उन्हें एक ख़तरनाक शत्रु मानते थे। बलपूर्वक आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाने की आवश्यकता के बारे में सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू से असहमत थे। वह मुक्त उद्यम में यक़ीन रखते थे। मार्च 1931 में पटेल ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के करांची अधिवेशन की अध्यक्षता की। गृहमंत्री बनने के बाद भारतीय रियासतों के विलय की ज़िम्मेदारी उन्हें ही सौंपी गई। उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए लगभग छह सौ छोटी-बड़ी रियासतों का भारत में विलय कराया। सरदार पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ। ■

भैरोंसिंह शेखावत

(23 अक्टूबर 1923 – 15 मई 2010)

भैरोंसिंह शेखावत भारत के ग्यारहवें उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। वे राजस्थान के राजनीतिक क्षितिज पर काफ़ी लम्बे समय तक छाये रहे। राजस्थान की राजनीति में उनका जबर्दस्त प्रभाव था। उनके कार्यकर्ताओं ने उन पर एक जोरदार नारा भी दिया, जो इस प्रकार था- "राजस्थान का एक ही सिंह, भेंरोसिंह..भेंरोसिंह। यह नारा बहुत लम्बे समय तक गूंजता रहा था। भैरोंसिंह शेखावत 1952 में विधायक बने। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलताएं अर्जित करते हुए विपक्ष के नेता, फिर मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति बने।

भैरोंसिंह शेखावत का जन्म 23 अक्टूबर 1923 को सीकर (राजस्थान) में हुआ। इनके पिता का नाम देवीसिंह और माता बन्ने कंवर थीं। भैरोंसिंह शेखावत ने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही प्राप्त की। हाईस्कूल करने के पश्चात् उन्होंने जयपुर के 'महाराजा कॉलेज' में दाखिला लिया। उन्होंने पुलिस की नौकरी भी

की, लेकिन उसमें मन नहीं रमा और त्यागपत्र देकर वापस खेती करने लगे। भैरोंसिंह शेखावत जनसंघ के संस्थापक काल से ही जुड़ गये और 'जनता पार्टी' तथा 'भाजपा' की स्थापना में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। वर्ष 1952 में वे दस रुपये उधार लेकर दाता रामगढ़ से चुनाव के लिए खड़े हुए। इस चुनाव में उन्हें सफलता मिली इस सफलता के बाद उनका राजनीतिक सफर लगातार चलता रहा। वे दस बार विधायक तथा 1974 से 1977 तक राज्य सभा के सदस्य रहे। अपने लम्बे राजनीतिक सफर में भैरोंसिंह शेखावत 1977 से 1980, 1990 से 1992 और 1993 से 1998 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और 2002 में भारत के उपराष्ट्रपति बने । भैरोंसिंह शेखावत का निधन 15 मई 2010 को हुआ। आजीवन राष्ट्रहित में काम करने वाले जन नेता शेखावत जी ग़रीबों के सच्चे सहायक थे। उन्होंने कहा कि मैं ग़रीबों और वंचित तबके के लिए काम करता रहूंगा ताकि वे अपने मौलिक अधिकारों का गरिमापूर्ण तरीक़े से इस्तेमाल कर सकें। ■

आज स्वच्छता अभियान बना एक आंदोलन : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। यह स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की तीसरी वर्षगांठ और 'स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़े के समापन का भी अवसर था। उन्होंने कहा कि दो अक्टूबर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है और यह एक ऐसा अवसर है जो हमें बताता है कि स्वच्छ भारत के लक्ष्य की दिशा में हम कितना सफर तय कर पाए हैं।

प्रधानमंत्री ने याद किया कि भारी आलोचना के बीच तीन साल पहले कैसे स्वच्छ भारत आंदोलन शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि वह इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि जो मार्ग महात्मा गांधी ने दिखाया है, वह गलत नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अगर कुछ चुनौतियां भी हैं तो उनका अर्थ यह नहीं है कि हम उनसे दूर भाग जाएं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज लोग एक स्वर में स्वच्छता के लिए अपनी इच्छा का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वच्छता को नेताओं और सरकारों के प्रयासों के माध्यम से हासिल नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे समाज के प्रयासों से प्राप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए जन-भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज स्वच्छता अभियान एक आंदोलन बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के दिन तक जो कुछ भी हासिल किया गया है, वह भारत के स्वच्छाग्रही लोगों की भी उपलब्धि है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर स्वराज को सत्याग्रहियों द्वारा हासिल किया गया, तो श्रेष्ठ भारत को स्वच्छाग्रहियों द्वारा हासिल किया जाएगा। शहरों की स्वच्छता रैंकिंग का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने एक सकारात्मक और प्रतिस्पर्धी वातावरण को विकसित किया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को भी विचारों में क्रांति की आवश्यकता है और प्रतिस्पर्धा स्वच्छता की अवधारणा के विचारों का एक मंच प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री ने उन सभी को बधाई दी जिन्होंने 'स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़े के दौरान योगदान दिया, लेकिन साथ ही कहा कि अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय निबंध, चित्रकारी और फिल्म प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए। साथ ही डिजिटल प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। ■

उपराष्ट्रपति का हर भारतीय से स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने का आह्वान

उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि हर भारतीय को स्वच्छ भारत अभियान में भागीदारी करनी चाहिए, जिससे 02 अक्टूबर,2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। श्री नायडू 2 अक्टूबर को इंडिया टुडे समूह द्वारा आयोजित इंडिया टुडे सफाईगिरी पुरस्कार-2017 वितरित करने के अवसर पर संबोधन कर रहे थे।

उपराष्ट्रपति श्री नायडू ने कहा कि गांधीजी ने स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी और उन्होंने कहा था कि "स्वच्छता राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। हमारी कई बीमारियों का कारण शौचालयों की स्थिति और शौच का उपयुक्त निपटाना न करने की गंदी आदत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा पूरा किया जा सकता है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि चलता है रवैया अपनाने से हम प्रगति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने के लिए हमें संयुक्त रूप से नए नवाचारों की की खोज जारी रखनी होगी। इस पवित्र अभियान के लिए हम सबको जिम्मेदारी निभानी होगी। ये महज एक कार्य या रोजमर्रा का कार्य नहीं है।

'आदिवासी देशभक्तों को पुष्पांजलि नहीं, कार्यांजलि दे रही है भाजपा'

मेरा मानना है कि देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में जनजाति और दलित समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उन्होंने अनेक बलिदान दिए, परन्तु दुर्भाग्यवश इतिहासकारों ने उन्हें वह मान्यता नहीं दी जिसके वह हकदार थे। अगर हम झारखंड की बात कहे तो भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धु कान्हु, नीलाम्बर, पीताम्बर, गया मुंडा और तेलंगा खडिया इत्यादि जैसे अनेक देशभक्त आदिवासी सूरमाओं ने देश के लिए बलिदान देकर झारखण्ड और मां भारती की सेवा की।

अमित शाह

पार्टी के संगठनात्मक कार्य के लिए आयोजित विस्तृत प्रवास के अंतर्गत मुझे हाल में भगवान बिरसा मुंडा की धरती झारखंड में तीन दिन बिताने का अवसर मिला। इसी दौरान 17 सितम्बर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाये जा रहे "सेवा दिवस" को मैं भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली को नमन करने खूंटी जिला स्थित उनके पैतृक गांव उलिहातू गया जहां मुझे उनके वंशजों को सम्मान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सेवा दिवस के अंतर्गत मुझे उलीहातू गांव के सर्वांगीण विकास की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। झारखण्ड सरकार ने उलीहातू जैसे शहीदों की जन्मभूमि रहे 19 गांवों के सर्वांगीण के विकास के लिए "शहीद ग्राम विकास योजना" बनाई है। इस योजना के अंतर्गत इन गावों की बिजली, पानी, सड़क, पक्का आवास, स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को आदर्श रूप से विकसित किया जाएगा। मेरा मानना है कि झारखंड सरकार ने पूर्व में पारंपरिक रूप से शहीदों को दी जाने वाली पुष्पांजलि को विकास का रंग देकर इसे कार्यांजलि में बदल दिया है। मैं झारखण्ड सरकार और उसके मुखिया श्री रघुबर दास को शहीदों को सम्मान देने के इस अनूठे प्रयास के लिए बधाई देता हूं।

मेरा मानना है कि देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में जनजाति और दलित समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उन्होंने अनेक बलिदान दिए, परन्तु दुर्भाग्यवश इतिहासकारों ने उन्हें वह मान्यता नहीं दी जिसके वह हकदार थे। अगर हम झारखंड की बात कहे तो भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धु कान्हु, नीलाम्बर, पीताम्बर, गया मुंडा और तेलंगा खडिया इत्यादि जैसे अनेक देशभक्त आदिवासी सूरमाओं ने देश के लिए बलिदान देकर झारखण्ड और मां भारती की सेवा

की। भगवान बिरसा मुंडा ने तो सिर्फ 20 वर्ष की अल्पायु में लगान माफी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आन्दोलन किया और दो वर्षों तक कारागार में रहे। जेल से बाहर आ कर उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए मुंडा सेना गठित की और अनेकों अवसरों पर अंग्रेजों के दांत खट्टे किये।

आज भारत में लगभग 9% आबादी आदिवासियों की है जो कि देश के हर कोने में विभिन्न नामों से जाने जाते है। हमारा देश तरह-तरह की संस्कृति, भाषाओं, वेश-भूषाओं और खान-पान का एक रंगीन गुलदस्ता है और हमारा आदिवासी समाज इस गुलदस्ते का सबसे अनिवार्य और सुन्दर पुष्प है। अपने सार्वजनिक जीवन में मुझे देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले आदिवासी भाइयों और बहनों से मिलने और उनकी जीवन शैली को नजदीक से देखने का अवसर मिला। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि हमारी सभ्यता के संवर्धन में आदिवासियों की अहम भूमिका है क्योंकि उन्होंने आज भी अपने रीति-रिवाजों को संभाल कर रखा है।

सुदूर इलाकों में बसने और पूर्व की सरकारों की उपेक्षा के कारण दुर्भाग्यवश हमारे आदिवासी समाज का अभी तक वांछित विकास नहीं हो सका है। पिछले 70 वर्षों में सरकारों ने प्राकृतिक और खनिज संपदा से परिपूर्ण आदिवासी इलाकों का दोहन तो खूब किया, परन्तु असंतुलित नीतियों की वजह से इस संपत्ति का लाभ इन इलाकों में रहने वालों का नहीं मिल पाया। जंगल और पहाड़ उजड़ते गए, परन्तु न तो वनवासियों क्षेत्रों के मूलभूत ढांचे को विकसित किया गया और न ही उनके पर्यावरण की सुरक्षा के प्रयास किये गए। वनवासियों से उनके प्राकृतिक संसाधन तो लगातार छीने जाते रहे, परन्तु बदले में न उन्हें रोजगार मिले और न ही उनका विकास हो पाया। परिणाम स्वरूप देश का आदिवासी विकास की दौड़ में बहुत पीछे छूट गया।

जल, जंगल और जमीन का संवर्धन पहले भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रही है। वास्तव में जनसंघ का जन्म ही "विकास के भारतीय मॉडल" के मुद्दे पर हुआ था, जिसके केंद्र में पाश्चात्य तर्ज पर विकास की अंधी दौड़ से हट कर भारतीय सभ्यता के संवर्धन के साथ विकास था। अतः भाजपा के वैचारिक मूल में ही जंगल और जनजातियों के विकास को प्राथमिकता दी गयी है। लम्बे समय तक सरकार में न रहने के बावजूद भाजपा और उसके वैचारिक परिवार के वनवासी कल्याण आश्रम जैसे अनेक संगठनों ने जनजातियों के विकास अविरल प्रयास किये हैं। पूर्व में जनजातीय विकास कार्यों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता था और इस विषय के लिए कोई समर्पित मंत्रालय नहीं था। यह पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सोच थी कि आदिवासियों के विकास के लिए उन्होंने एक पृथक "जनजातीय कार्य मंत्रालय" की स्थापना 1999 में की।

केंद्र की मोदी सरकार ने जनजातियों के विकास के लिए कई कदम उठाये हैं, जिनमे से सबसे प्रमुख 2014 में शुरू की गई "वनबन्धु कल्याण योजना" है, जिसके अंतर्गत जनजाति आबादी वाले विकास प्रखंडों में अनेक काम किये जा रहे हैं। जैसाकि मैनें पहले भी कहा कि जनजाति इलाकों की प्राकृतिक संपदा का लाभ स्वयं को न मिल पाना इन क्षेत्रों के विकास में प्रमुख बाधा रहा है। मोदी सरकार ने इस नीतिगत विसंगति का संज्ञान लेते हुए The Mines and Mineral (Development and Regulation) Act, 1957 में संशोधन करके 2015 में District Mineral Foundation (DMF) की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य खनन से प्रभावित क्षेत्रो के कल्याण के लिए काम करना है। जिसके अंतर्गत खनन से होने वाली आय की 10% रॉयल्टी कोष से "प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना" (PMKKKY) 2015 में शुरू की गई है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अभी तक District Mineral Foundation (DMF) में 9,100 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं, जो कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में जहां बहुतायत आदिवासी रहते हैं, के विकास में खर्च किये जायेंगे।

आज भारत में लगभग 9% आबादी आदिवासियों की है जो कि देश के हर कोने में विभिन्न नामों से जाने जाते है। हमारा देश तरह-तरह की संस्कृति, भाषाओं, वेश-भूषाओं और खान-पान का एक रंगीन गुलदस्ता है और हमारा आदिवासी समाज इस गुलदस्ते का सबसे अनिवार्य और सुन्दर पुष्प है।

मेरे गृह प्रदेश गुजरात में भी 14 जनजाति बाहुल्य जिले हैं। भाजपा की गुजरात सरकार ने लम्बे समय से आदिवासियों के विकास के लिए प्रयास किये हैं और मुझे बताते हुए असीम संतोष है कि आज प्रदेश के बजट का 14.75% सिर्फ जनजातियों के विकास के लिए समर्पित है। भाजपा सरकारों के प्रयास का फल है कि गुजरात के जनजाति क्षेत्र विकास के किसी भी पैमाने में प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से पीछे नहीं है।

समस्त देश के साथ जनजातियों को भी 1947 में अंग्रेजों से स्वराज तो मिल गया, परन्तु जनजातियों के वास्तविक स्वराज का समय अब आया है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कटिबद्ध है।

मुझे पूर्ण विश्वास है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार जिस तरह से काम कर रही है उससे पूर्वोत्तर के साथ-साथ संपूर्ण देश में जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास होगा और उनकी स्वराज से सुराज की यात्रा शीघ्र पूरी होगी। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं)

जल पर संवेदनशील बने समाज

जल प्रबंधन से जुड़े पहलुओं पर सार्थक चर्चा के लिए भारत में भी वर्ष 2012 से वार्षिक नीतिगत संवाद भारत जल सप्ताह की शुरुआत हुई है। इस साल भी भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरोद्धार मंत्रालय के तत्वाधान में इसके पांचवें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। 10 से 14 अक्टूबर तक होने वाले इस आयोजन की थीम है- 'समावेशी विकास के लिए जल और ऊर्जा।'

अर्जुन राम मेघवाल

दुनिया पानी को लेकर विकराल संकट से जूझ रही है तो भारत भी इससे अछूता नहीं है। हालात यहां तक पहुंच गए कि संयुक्त राष्ट्र को 1993 में 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित करना पड़ा। इसका प्रयोजन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में सभी सरकारों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ मिलकर जल संकट समाधान के लिए मिलकर काम करने से है। इसी अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा सहस्त्राब्धि विकास लक्ष्यों यानी एमडीजी के बाद सितंबर, 2015 में जिस सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी को चुना गया, उसमें भी मानव अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी जल को लेकर विशेष ध्यान दिए जाने पर जोर दिया गया है। इन चुनौतियों का तोड़ निकालने के बीच अब विभिन्न मंचों पर जलवायु परिवर्तन की चिंता पर चर्चा भी आम हो गई है।

जल प्रबंधन से जुड़े पहलुओं पर सार्थक चर्चा के लिए भारत में भी वर्ष 2012 से वार्षिक नीतिगत संवाद भारत जल सप्ताह की शुरुआत हुई है। इस साल भी भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरोद्धार मंत्रालय के तत्वाधान में इसके पांचवें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। 10 से 14 अक्टूबर तक होने वाले इस आयोजन की थीम है-'समावेशी विकास के लिए जल और ऊर्जा।' मैं इस दिशा में तत्काल कदम उठाने की हिमायत इसलिए करता हूं, क्योंकि बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन बेहद सीमित हैं। अंधाधुंध दोहन से वे तेजी से सिकुड़ते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी एफएओ के अनुसार पेयजल के लिए भले ही रोजाना प्रति व्यक्ति 2 से 4 लीटर पानी की जरूरत पड़ती हो, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए एक दिन का भोजन तैयार करने में 3,000 से 5,000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। उसका अनुमान है कि वर्ष 2050 तक वैश्विक जल संपदा पर 2.7 अरब की अतिरिक्त आबादी के भरण-पोषण का बोझ भी पड़ने वाला है। भारत में भी प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 2010 में 1608 घन मीटर के मुकाबले 2050 तक घटकर 1139 घन मीटर रह जाएगी। चूंकि विकास के मोर्चे पर भारत तेजी से छलांग लगा रहा है, जिससे पानी की जरूरत भी बढ़ेगी, ऐसे

में यहां जल का समुचित प्रबंधन उतना ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल देश की आधी से अधिक कामकाजी आबादी खेती से जुड़ी है जिसमें सिंचाई की अहम भूमिका है। भारत में जल संसाधनों का 85 फीसद सिंचाई में उपयोग होता है। मानसून की बिगड़ी चाल और वर्षा के असमान वितरण से जहां बुंदेलखंड, विदर्भ, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ इलाके सूखे की मार झेल रहे हैं तो असम, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे देश के कई इलाके बाढ़ की विभीषिका से परेशान हैं। यह असंतुलन न केवल कृषि, बल्कि ग्रामीण विकास, पर्यावरण, विनिर्माण और कारोबारी सेवाओं को भी प्रभावित कर रहा है जिसका खामियाजा अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ रहा है।

आवश्यकता है कि इस दुर्लभ संसाधन के संरक्षण के लिए गंभीर और सतत प्रयास किए जाएं जिसमें राज्य सरकारों, पंचायती राज संस्थानों, सामुदायिक संस्थानों और पारिवारिक से लेकर वैयक्तिक स्तर पर भागीदारी जरूरी होगी। जल संसाधन प्रबंधन के लिए सरकार ने कुल 30 लिंक चिन्हित किए हैं, जहां अधिशेष जलराशि वाले इलाकों से पानी किल्लत वाले क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा। इस योजना में 16 लिंक प्रायद्वीपीय भारत और 14 हिमालयी क्षेत्र में हैं। नदियों को जोड़ना मौजूदा सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है, जिसमें अधिशेष वाले क्षेत्रों से 170 अरब घन मीटर पानी को किल्लत वाले क्षेत्रों में पहुंचाने का लक्ष्य है। इससे 3.5 करोड़ अतिरिक्त भूमि सिंचित होगी। बाढ़ से निजात के अलावा नौवहन, पेयजल सहित तमाम मोर्चों पर सहायता मिलेगी। देश में जल प्रबंधन को तार्किक और संतुलित बनाने के लिए हमें पानी की आपूर्ति और उसके वितरण की नए सिरे से समीक्षा करनी होगी।

सड़क, रेल और कई अन्य माध्यमों में निवेश की तुलना में सिंचाई में हुआ निवेश कहीं ज्यादा जल्दी फलीभूत होता है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आगाज किया। 'पर ड्रॉप, मोर क्रॉप' यानी कम सिंचाई में अधिक फसल को सरकार ने अपना मंत्र बनाया है। इसमें सूखा प्रभावित क्षेत्रों को तरजीह दी जा रही है। राज्य और जनपद स्तर की योजनाओं में सिंचाई की मद में किए जाने निवेश को साथ जोड़ते हुए इस योजना को सिरे चढ़ाया जा रहा है। पूरा ध्यान खेत में पानी के बेहतर उपयोग और सिंचाई क्षमता और उपयोगिता में खाई पाटने पर है। समग्र-एकीकृत दृष्टिकोण के साथ जल क्रांति अभियान जैसी योजना भी सभी पक्षों की भागीदारी के साथ लागू हो रही है, जिसका मकसद जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना है। सरकार ने नेशनल वॉटर इन्फोर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना की जो जल संसाधनों के राष्ट्रव्यापी आंकड़े तैयार करेगा।

नदियों की सफाई एक अनवरत प्रक्रिया है। इसमें नमामि गंगे परियोजना उम्दा उदाहरण है। इसके तहत विभिन्न तरह की गतिविधियों वाली 173 योजनाएं संचालित हो रही हैं, जिसमें घाटों की सफाई से लेकर गांव-शहरों की स्वच्छता भी शामिल है। 173 में 41 परियोजनाएं तो पूरी भी हो चुकी हैं। गंगा में गंदगी फैलाने वाले उद्योगों पर सरकारी सख्ती का ही असर है कि गंगा में प्रवाहित होने वाले प्रदूषकों की तादाद में 35 प्रतिशत की कमी आई है। देश भर में बांध सुरक्षा के लिए भी बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना यानी डीआरआइपी चलाई जा रही है। चूंकि पानी का मसला संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची में आता है, ऐसे में अंतर-राज्य जल विवाद और उनका उचित समाधान केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। अंतर-राज्य नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत विवादों को सुलझाने के लिए वर्तमान में 8 ट्रिब्यूनल हैं। सरकार संशोधित राष्ट्रीय जल नीति पर काम कर रही है, जिसमें केंद्रीय स्तर पर एक स्थाई जल विवाद ट्रिब्यूनल बनाने के साथ ही विवाद समाधान समिति बनाने की योजना है जो राज्यों के जल संबंधी विवादों का समाधान निकालेगी। इसके लिए 1956 के कानून में संशोधन के मकसद से सरकार इस साल लोकसभा में नया विधेयक पेश भी कर चुकी है।

पानी के पुनः उपयोग को लेकर विभिन्न मंत्रालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, राज्य सरकारों और अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। जाहिर है जल संसाधनों के सतत विकास के लिए मौजूदा सरकार ने तमाम प्रयास किए हैं और जब इन प्रयासों को सभी वर्गों का साथ मिलेगा तो भारत निश्चित रूप से जल को लेकर संवेदनशील समाज बन जाएगा।

जल प्रबंधन के लिए सरकार के कई मंत्रालय और विभाग भी कंधे के कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। सीवेज पाइपलाइन से लेकर शौचालय निर्माण और प्लंबर का कौशल सिखाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से करार भी किया है। पानी के पुनः इस्तेमाल को लेकर रेल मंत्रालय और इंडियन ऑयल के साथ भी योजना बनाई है। बिजली मंत्रालय ने तो संयंत्रों के लिए अनिवार्य किया है कि वे सीवेज संयंत्र के 50 किलोमीटर की परिधि में मौजूद हों तो बिजली बनाने के लिए उसके पानी का ही इस्तेमाल करें। पानी के पुनः उपयोग को लेकर विभिन्न मंत्रालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, राज्य सरकारों और अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। जाहिर है जल संसाधनों के सतत विकास के लिए मौजूदा सरकार ने तमाम प्रयास किए हैं और जब इन प्रयासों को सभी वर्गों का साथ मिलेगा तो भारत निश्चित रूप से जल को लेकर संवेदनशील समाज बन जाएगा। ■

(लेखक केंद्रीय जल संसाधन राज्यमंत्री हैं) नवभारत टाइम्स से साभार

मजबूत है देश की अर्थव्यवस्था : नरेंद्र मोदी

द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के स्वर्ण जयंती वार्षिक समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकास के लिए और बड़े फैसले लेंगे और चुनावी फायदे के लिए देश का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते। श्री मोदी ने जीएसटी और नोटबंदी के मुद्दे पर बोलते हुआ कहा कुछ लोग कर्ण के सारथी शल्य की तरह निराश करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। यहां प्रस्तुत है उनके संबोधन के मुख्य अंश का प्रथम भाग:

द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) के स्वर्ण जयंती वार्षिक समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 4 अक्टूबर को कहा कि हमारे देश में भी मुट्ठीभर लोग ऐसे हैं जो देश की प्रतिष्ठा को, हमारी ईमानदार सामाजिक संरचना को कमजोर करने का काम करते रहते हैं। इन लोगों को सिस्टम और संस्थाओं से हटाने के लिए सरकार ने पहले ही दिन से 'स्वच्छता अभियान' शुरू किया हुआ है और इस 'स्वच्छता अभियान' के तहत सरकार बनते ही SIT बनाई गई, जो सुप्रीम कोर्ट ने कई वर्षों पहले कहा था। हमारी सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट में वो काम कर दिया है।

श्री मोदी ने कहा कि विदेश में जमा काले धन के लिए बहुत कठोर ब्लैक मनी एक्ट बनाया गया। कई नए देशों के साथ कर संधियां की गईं और पुराने टैक्स समझौतों में बदलाव किया गया। उनके साथ बैठ करके नए तरीके ढूंढे। इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड बनाया गया। 28 साल से अटका हुआ बेनामी संपत्ति कानून लागू किया गया। कई वर्षों से लटका हुआ गुड एंड सिम्पल टैक्स -GST लागू किया गया। विमुद्रीकरण का फैसला लेने की हिम्मत भी इसी सरकार ने दिखाई।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सरकार ने देश में संस्थागत ईमानदारी को मजबूत करने के लिए काम किया है। ये सरकार के अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि आज देश की अर्थव्यवस्था कम कैश के साथ चल रही है। विमुद्रीकरण के बाद कैश टू जीडीपी रेश्यो 9% आ गया है।

श्री मोदी ने कहा कि 9 नवम्बर, इतिहास में भ्रष्टाचार मुक्ति के अभियान का प्रारम्भ दिवस माना जाएगा, 8 नवम्बर, 2016 से पहले ये रेश्यो 12% था आज 9% है। अगर देश में, देश की अर्थव्यवस्था में ईमानदारी का नया दौर शुरू नहीं हुआ होता तो क्या ये संभव था? और आपसे अच्छा इसको कौन जानता है कि पहले जिस तरह आसानी से ब्लैक मनी का लेन-देन होता था, अब वैसा करने में पहले लोगों को 50 बार सोचना पड़ता है और मुझसे ज्यादा आप जानते हैं इस बात को।

उन्होंने कहा कि महाभारत में ही एक और किरदार थे; शल्य का नाम सुना होगा आपने? ये शल्य वैसे कर्ण के सारथी थे। उधर अर्जुन के साथ कृष्ण थे, इधर कर्ण के सारथी शल्य थे, लेकिन ये शल्य जो भी युद्ध में था, उनको हतोत्साहित करने का ही काम करता। उससे क्या लड़ोगे, तुम्हारे पास तो कोई दम नहीं है, अरे, तुम्हारे घोड़े में दम नहीं है। अब ये शल्य इंसान ही ऐसा नहीं है, शल्य वृत्ति है और कोई महाभारत के युग में ही ऐसा नहीं, आज के युग में भी है। कुछ नहीं

होगा, कैसे करोगे?

श्री मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को निराशा फैलाने में बड़ा आनंद आता है, उनको रात को बहुत अच्छी नींद आती है और ऐसे लोगों के लिए आजकल एक तिमाही की ग्रोथ कम होना, जैसे सबसे बड़ी खुराक मिल गया है। अब ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। ऐसे लोगों को जब डाटा अनुकूल होता है, तो उन्हें वो इंस्टीट्यूट भी अच्छे लगते हैं, वो प्रोसेस भी सही लगता है, लेकिन जैसे ही ये डाटा उनकी कल्पना के प्रतिकूल होता है, तो ये कहते हैं संस्थान ठीक नहीं है, प्रोसेस ठीक नहीं है, करने वाले ठीक नहीं हैं, भांति-भांति के आरोप लगाते हैं। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। ये शल्य वृत्ति को जब तक हम नहीं जानेंगे, हम सत्य के रास्ते की जो सोच रहे हैं ना- सत्यम वद्।

उन्होंने कहा कि साथियों क्या आपको लगता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में जीडीपी की ग्रोथ किसी तिमाही में 5.7 प्रतिशत तक

पहुंची है? क्या ये पहली बार हुआ है क्या? पिछली सरकार में 6 साल में 8 बार ऐसे मौके आए, जब विकास दर 5.7 प्रतिशत या उससे नीचे गिरी थी। देश की अर्थव्यवस्था ने ऐसे तिमाही भी देखे हैं, जब विकास दर, भूलिए मत पुरानी बातों को, जब विकास दर 0.2 प्रतिशत, 1.5 प्रतिशत, यहां तक गिरी थी। ऐसी गिरावट अर्थव्यवस्था के लिए और ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उस कालखंड में, इन वर्षों में जब ये ग्रोथ दर इतनी नीचे गिरी थी, भारत हायर इन्फ्लेशन, हायर करेंट अकाउंट डेफिसिट और हायर फिस्कल डेफिसिट से जूझ रहा था। ऐसी संकट की घड़ी में ये हाल हुआ था।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर 2014 के पहले के दो वर्ष, यानी साल 2012-13 और और 13-14 देखें तो औसत वृद्धि 6 प्रतिशत के आसपास थी। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि आपने दो ही साल क्यों लिए? क्योंकि आजकल शल्य वृत्ति कुछ भी काम कर सकती है। दो साल का संदर्भ मैंने इसलिए लिया, क्योंकि इस सरकार के तीन साल और पिछली सरकार के आखिरी के दो सालों में जीडीपी डाटा तय करने का तरीका एक ही रहा है।

उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशन से प्रोसेस से, और इसलिए तुलना करना स्वाभाविक, सरल होता है। जब Central Statistics Office ने इस सरकार के दौरान जीडीपी में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि का डाटा जारी किया था, तो इन्ही लोगों ने इसे खारिज कर दिया था और क्या कहा था कि ग्राउंड रियल्टी में हमें ऐसा लग नहीं रहा है। हमारी जो शल्य वृत्ति है, उसमें ये फिट नहीं होता है।

श्री मोदी ने कहा कि वो ही इंस्टीट्यूशन उस समय पंसद नहीं थे, पद्धति पसंद नहीं थी, लेकिन 5.6 हुआ; एकदम मजा आ गया। हां ये इंस्टीट्यूशन अच्छी है और ऐसे लोग कहते थे कि उन्हें फील नहीं हो रहा। अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, ये हमारे गले नहीं उतरता है।

उन्होंने कहा कि इसलिए इन चंद लोगों ने ये प्रचार शुरू कर दिया कि जीडीपी तय करने के तरीके में कुछ गड़बड़ है। तब ये लोग डाटा के आधार पर नहीं, अपनी फीलिंग पर बातें कर रहे थे और इसलिए उन्हें अर्थव्यवस्था में विकास होता नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही पिछले दो तिमाही में विकास दर 6.1 और 5.7 प्रतिशत हुई, इन्हीं शल्य वृत्ति को ये डाटा बहुत प्यारा लगने लगा, बहुत भाने लगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं न कोई अर्थशास्त्री हूं और न ही कभी मैंने अर्थशास्त्री होने का दावा किया है, लेकिन आज जब ये अर्थव्यवस्था पर इतनी चर्चा हो रही है, तो मैं आपको जरा फ़्लैश बैक में भी लेकर जाना चाहता हूं। एक वो दौर था जब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारत को एक नए ग्रुप का हिस्सा बनाया गया था और ये नया ग्रुप यानी आपको लगता होगा- G7 होगा, G8 होगा, G20 होगा, इसमें कहीं रखा होगा, जी नहीं। इस ग्रुप का नाम था फ्रैजाइल फाइव।

उन्होंने कहा कि इसे ऐसा डेंजरस ग्रुप माना गया था जिसकी खुद की अर्थव्यवस्था तो एक समस्या थी, लेकिन दुनिया को लग रहा था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की रिकवरी में भी ये बाधा बन रहे हैं और उसमें भारत का नाम था। यानी हमारा काम ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम औरों का भी बुरा करेंगे, ये इसलिए फ्रैजाइल फाइव के ग्रुप में ये भारत का नाम जोड़ दिया गया था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे जैसे अर्थशास्त्र के कम जानकार को अब भी ये समझ नहीं आ रहा है कि उस समय बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों के रहते ऐसा कैसे हो गया? आपको ये अवश्य याद होगा कि हमारे देश में उस समय जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा इन्फ्लेशन में ग्रोथ थी, इसी की चर्चा होती थी। फिस्कल डेफिसिट और करेंट अकाउंट डेफिसिट में ग्रोथ पर चर्चा प्रमुख रहती थी।

उन्होंने कहा कि रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में ग्रोथ होने पर अखबारों में मुख्य खबरें बना करती थीं। यहां तक की ब्याज दर में ग्रोथ भी सभी की चर्चा में शामिल हुआ करता था। देश के विकास को विपरीत दिशा में ले जाने वाले ये सभी पैरामीटर्स तब कुछ लोगों को पसंद आते थे। अब जब वही पैरामीटर्स सुधरे हैं, विकास को सही दिशा

विदेश में जमा काले धन के लिए बहुत कठोर ब्लैक मनी एक्ट बनाया गया। कई नए देशों के साथ कर संधियां की गईं और पुराने टैक्स समझौतों में बदलाव किया गया। उनके साथ बैठ करके नए तरीके ढूंढे। इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड बनाया गया। 28 साल से अटका हुआ बेनामी संपत्ति कानून लागू किया गया। कई वर्षों से लटका हुआ गुड एंड सिम्पल टैक्स -GST लागू किया गया।

मिली है तो ऐसे कुछ लोगों ने आंखों पर पर्दा डाल लिया है। इस पर्दे के कारण उन्हें दीवार पर स्पष्ट लिखी चीजें भी नहीं दिखाई दे रही हैं और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 10 प्रतिशत से ज्यादा की इन्फ्लेशन कम होकर अब इस साल औसतन 2.5 प्रतिशत पर आ गई है। कहां 10 कहां अढ़ाई? लगभग 4 प्रतिशत का करेंट अकाउंट डेफिसिट, औसतन 1 प्रतिशत के आसपास आ गया है। आप देख सकते हैं। इन सारे पैरामीटर्स को सुधारते समय, केंद्र सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट पिछली सरकार के 4.5% प्रतिशत से घटाकर 3.5% प्रतिशत पर ले आई है। आज विदेशी निवेशक भारत में रिकॉर्ड निवेश कर रहे हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 30 हजार करोड़ डॉलर से बढ़कर 40 हजार करोड़ डॉलर के पार कर गया है। 25 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में ये सुधार, ये विश्वास, ये सफलताएं शायद उनकी नजर में मायने नहीं रखती हैं। इसलिए देश के लिए अभी

ये सोचने का समय है कि कुछ लोग देश हित साध रहे हैं या किसी और का हित साध रहे हैं। ये बात सही है कि पिछले तीन वर्षों में 7.5 प्रतिशत की औसत ग्रोथ हासिल करने के बाद इस वर्ष अप्रैल-जून की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ में कमी दर्ज की गई, हम इसको इंकार नहीं करते हैं, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि सरकार इस ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, क्षमतावान है और हम फैसले लेने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि कई जानकारों ने इस बात पर सहमति जताई है कि देश की अर्थव्यवस्था के fundamentals मजबूत हैं। हमने सुधार से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। देश की फाइनेंसियल स्टेबिलिटी को भी मेन्टेन रखा जाएगा। निवेश बढ़ाने के और आर्थिक विकास को गति देने के लिए हम हर आवश्यक कदम उठाते रहेंगे।

श्री मोदी ने कहा कि मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा लिए गए कदम, देश को आने वाले वर्षों में विकास की एक नई लीग में रखने वाले हैं। आज भी रिजर्व बैंक ने कहा है कि अगली तिमाही के जो आने वाले हैं, आंकड़े की संभावना बताई है, उन्होंने बढ़ते-बढ़ते 7.7 तक ले जाएगा, ये आज रिजर्व बैंक ने भी अनुमानित किया है।

10 प्रतिशत से ज्यादा की इन्फ्लेशन कम होकर अब इस साल औसतन 2.5 प्रतिशत पर आ गई है। कहां 10 कहां अढ़ाई? लगभग 4 प्रतिशत का करेंट अकाउंट डेफिसिट, औसतन 1 प्रतिशत के आसपास आ गया है। आप देख सकते हैं। इन सारे पैरामीटर्स को सुधारते समय, केंद्र सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट पिछली सरकार के 4.5% प्रतिशत से घटाकर 3.5% प्रतिशत पर ले आई है।

श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान में अगर इन मूलभूत सुधारों की वजह से किसी सेक्टर को तत्काल सहायता की आवश्यकता है, तो सरकार उसके प्रति सजग भी है और वो चाहे MSME हो, या एक्सपोर्ट सेक्टर हो या फिर हमारी नॉन-फॉर्मल इकॉनमी का हिस्सा और आज इस मंच पर मैं अपनी एक बात फिर दोहराना चाहूंगा और आपके माध्यम से जल्दी पहुंचेगा कि बदलती हुई देश की इस अर्थव्यवस्था में अब ईमानदारी को लाभ मिलेगा। ईमानदारों के हितों की सुरक्षा की जाएगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं ये जानता हूं कि जो लोग अब मुख्यधारा में लौट रहे हैं, ऐसे कुछ व्यापारियों के मन में एक डर रहता है कि कहीं ये नए कारोबार को देख करके पुराने की कल्पना कर करके पुराने रिकॉर्ड तो नहीं खंगाले जाएंगे? मैं फिर एक बार विश्वास दिलाता हूं ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि पहले सरकार, सरकारों के नियम, लोगों का आचरण ऐसा था, ये सब शायद करना पड़ा होगा और उसके कारण अब आपको सही धारा में आने से रोकना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है और इसलिए हमारी सरकार का इरादा है कि जितने लोग ईमानदारी की मुख्यधारा में आना चाहते हैं, उनके लिए स्वागत है और पुरानी चीजों को वहीं छोड़ करके आइए। आप चिंता मत कीजिए, आगे के लिए हम आपके साथ रहेंगे।

श्री मोदी ने कहा कि उसी प्रकार से मैं आज GST के संबंध में भी कहना चाहता हूं। तीन महीने हुए। तीन महीने के बाद क्या हो रहा है, क्या नहीं; हर चीज को हमने भली-भांति देखा है। बारीक से बारीक चीजों के फीडबैक लिए हैं और GST कौंसिल की मीटिंग के लिए मैंने उनसे कहा है कि अब तीन साल हो गए हैं, हम पूरी तरह उसका रिव्यु करें, और जहां-जहां कठिनाइयां हैं, व्यापारी वर्ग को दिक्कत है, तकनीक की दिक्कत है, फॉर्म भरने की दिक्कत है, जो भी दिक्कत है; उसको एक बार रिव्यु किया जाए और सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी सरकारें, क्योंकि सभी राज्य सरकारों में कोई न कोई पॉलिटिकल पार्टी है- मिल करके क्या बदलाव करने की आवश्यकता होगी, उस पर करें और मैं देश के व्यापारी वर्ग को विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम लकीर के फकीर नहीं हैं और हम कभी ये दावा नहीं करते हैं सब ज्ञान हमको ही है, लेकिन सही दिशा में जाने का प्रयास है। जहां कहीं रुकावटें हैं, तीन महीने में जो अनुभव आया है, उसके आधार पर आवश्यक जो भी बदलाव करना होगा, सुधार करना होगा, ये सरकार आपके साथ है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे पक्का यकीन है कि जब आपने अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी, मैं नहीं मानता हूं कि आपमें से किसी ने उसे मजबूरी में खरीदा होगा। गाड़ी खरीदने से पहले आपने रसोई का बजट देखा होगा, बच्चों की पढ़ाई का खर्च देखा होगा, बड़े-बुजुर्गों की दवाई का खर्च देखा होगा और इसके बाद अगर पैसे बचते हैं, तब जाकर घर या गाड़ी के बारे में सोचा होगा। सीधी-सीधी बात है? ये हमारे समाज की बहुत बेसिक सोच है कि ऐसे में अगर देश में जून महीने के बाद पैसेंजर कारों की बिक्री में लगभग 12 प्रतिशत वृद्धि हुई हो, तो आप

उसको क्या कहेंगे भाई?

श्री मोदी ने कहा कि आप क्या कहेंगे जब आपको पता चलेगा कि जून के बाद कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री में 23 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि हुई है? आप क्या कहेंगे जब देश में दो पहिया वाहनों की बिक्री में 14 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि हुई है। आप क्या कहेंगे जब डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक, हवाई जहाज में जाने वाले यात्रा करने वालों की संख्या में पिछले दो महीने में 14 प्रतिशत वृद्धि हुई है। आप क्या कहेंगे जब अंतरराष्ट्रीय Air freight (फ्रेट) ट्रैफिक यानी हवाई जहाज के जरिए माल ढुलाई में लगभग 16 प्रतिशत वृद्धि हुई है। आप क्या कहेंगे जब देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं में 14 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा कि ये वृद्धि संकेत दे रही हैं कि लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, फोन कनेक्शन ले रहे हैं, हवाई यात्राएं कर रहे हैं। ये इंडीकेटर्स शहरी क्षेत्रों में मांग की ग्रोथ को दर्शाते हैं। अब अगर ग्रामीण मांग से जुड़े, इंडीकेटर्स को देखें तो हाल के महीनों में ट्रैक्टर की बिक्री में 34 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा कि FMCG के क्षेत्र में भी डिमांड-ग्रोथ का ट्रेंड सितंबर महीने में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा तब होता है जब देश के लोगों का विश्वास बढ़ता है। जब देश के लोगों को लगता है कि अर्थव्यवस्था मजबूत है। अभी रिलीज हुआ PMI का Manufacturing Index Expansion Mode ये दर्शा रहा है कि Future Output Index तो 60 का आंकड़ा पार कर चुका है। हाल में आए आंकड़ों को देखें तो कोयले, बिजली, स्टील और नेचुरल गैस से उत्पादन में भी काफी अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है।

श्री मोदी ने कहा कि पर्सनल लोन के वितरण में भी तेज वृद्धि देखी जा रही है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और Non-Banking फाइनेंस कंपनीज के द्वारा दिए गए लोन में भी काफी वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, कैपिटल मार्केट में अब म्यूच्यूअल फंड और बीमा में अधिक निवेश हो रहा है।

श्री मोदी ने कहा कि कंपनियों ने IPO's के द्वारा इस साल पहले 6 महीने में ही 25 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जुटाई की है। पिछले साल पूरे वर्ष में ये राशि 29 हजार करोड़ तक ही पहुंची थी। Non-Financial Entities में कॉरपोदर बॉन्ड और प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा सिर्फ चार महीने में ही 45 हजार करोड़ रुपयों का निवेश किया गया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सारे आंकड़े देश में फाइनेंसिंग के ब्रॉड बेस को दर्शाते हैं, यानी भारत में अब फाइनेंसिंग केवल बैंकों के लोनों तक ही सीमित नहीं रह गई है। इस सरकार ने समय और संसाधन, दोनों के द्वारा उसके सही इस्तेमाल पर लगातार जोर दिया है। पिछली सरकार के तीन साल के काम की रफ्तार और हमारी सरकार के तीन साल के काम की रफ्तार का फर्क आपको साफ-साफ आयेगा।

श्री मोदी ने कहा कि ये सड़कें देख लीजिए, पिछली सरकार के आखिरी तीन सालों में गांवों में 80 हजार किलोमीटर सड़क बनी थी। हमारी सरकार के तीन साल में 1 लाख 20 हजार किलोमीटर सड़क बनाई है, यानी 50 प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है। पिछली सरकार ने अपने आखिरी के तीन साल में 15 हजार किलोमीटर नेशनल हाइवेज बनाने के काम दिया गया था।

मैं देश के व्यापारी वर्ग को विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम लकीर के फकीर नहीं हैं और हम कभी ये दावा नहीं करते हैं सब ज्ञान हमको ही है, लेकिन सही दिशा में जाने का प्रयास है। जहां कहीं रुकावटें हैं, तीन महीने में जो अनुभव आया है, उसके आधार पर आवश्यक जो भी बदलाव करना होगा, सुधार करना होगा, ये सरकार आपके साथ है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने अपने तीन साल में 34 हजार किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाइवेज बनाने का काम दिया गया है। कहां 15 हजार, कहां 34 हजार। अगर इसी सेक्टर में निवेश की बात की जाए, तो पिछली सरकार ने अपने आखिरी के तीन वर्षों में भूमि लेने और सड़कों के निर्माण पर 93000 करोड़ की राशि खर्च की थी। इस सरकार में ये राशि बढ़कर 1 लाख 83000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। यानी लगभग दोगुना निवेश इस सरकार ने करके दिखाया है। आपको भी पता होगा कि हाइवेज के निर्माण में सरकार को कितने प्रशासनिक और वित्तीय कदम उठाने पड़ते हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि कैसे सरकार ने पॉलिसी पैरालिसिस से निकल करके पॉलिसी मेकर और पॉलिसी इम्प्लीमेंटर का रोल अदा करके दिखाया है। ■

'हमें विश्व में सबसे तेज गति से बढ़नेवाली अर्थव्यवस्था बनने से कोई रोक नहीं सकता'

केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शॉर्ट टर्म गेन की जगह लॉन्ग टर्म गेन के लिए नीतियां बनाने और उसके इम्प्लीमेंटेशन को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की नीतियां देश को 30 साल तक एक स्टेबल पॉलिसी देने की दिशा में आगे बढ़ रही है और सभी फैसले इसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लिए जा रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 9 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को संबोधित किया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की हो रही आर्थिक प्रगति पर विशेष रूप से चर्चा की। उन्होंने फिक्की से बदलते हुए सामयिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य में अपनी भूमिका में बदलाव लाने की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि फिक्की ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक भारत की अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उन्होंने कहा कि फिक्की ने नीति-निर्धारकों और जिनके लिए नीतियां बनती हैं, उनके बीच एक सफल माध्यम बनने का सार्थक प्रयास किया है।

श्री शाह ने कहा कि 2014 से पहले 10 सालों तक देश में कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार थी और इस सरकार के दौरान देश में सर्वत्र निराशा का माहौल था। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान अर्थव्यवस्था लगातार नीचे जा रही थी, विकास दर 4% के आस-पास आ गया था, वित्तीय घाटा 5% से ज्यादा हो गया था, करेंट एकाउंट डेफिसिट भी 5% के लगभग हो गई थी, महंगाई दर अपने चरम पर थी। साथ थी,

घोटालों और भ्रष्टाचार ने देश को झकझोर कर रख दिया था। उन्होंने कहा कि उस वक्त सरकार की कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई थी। हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री समझता था और प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री मानने को तैयार ही नहीं था। उन्होंने कहा कि मीडिया वर्गों ने भी मान लिया था कि सरकार पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रस्त है। उन्होंने कहा कि जहां एनडीए की श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय पूरी दुनिया यह मानने लगी थी कि 21वीं सदी भारत की सदी है, वहीं यूपीए सरकार के समय देश का भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगा था। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में देश की जनता ने 30 साल बाद देश में एक पूर्ण बहुमत की सरकार का गठन किया और देश के विकास की बागडोर श्री नरेन्द्र मोदी के हाथों में सौंपने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि आज फिर से दुनिया यह मानने लगी है कि 21वीं सदी भारत की सदी है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शॉर्ट टर्म गेन की जगह लॉन्ग टर्म गेन के लिए नीतियां बनाने और उसके इम्प्लीमेंटेशन को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की नीतियां देश को 30 साल तक एक स्टेबल पॉलिसी देने की दिशा में आगे बढ़ रही है और सभी फैसले इसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जीडीपी के प्रति सरकार के दृष्टिकोण को भी बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जीडीपी को पहले कृषि विकास सेवा और औद्योगिक विकास के साथ जोड़ा जाता था। इन्फ्रास्ट्रक्चर के महत्व को भी सीमित कर दिया गया था, हमने इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देश की जीडीपी के साथ जोड़ने का काम किया। उन्होंने कहा कि यदि सड़कों का निर्माण होता है, टॉयलेट बनते हैं, घरों में बिजली और गैस सिलिंडर पहुंचाए जाते हैं, तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार होने के साथ-साथ देश की जीडीपी में भी बढ़ोतरी होती है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने देश के 30 करोड़ जन-धन अकाउंट ओपन कर समाज के गरीब-से-गरीब लोगों को देश के अर्थतंत्र की मुख्यधारा के साथ जोड़ने का सफल प्रयास किया है। मुद्रा बैंक के माध्यम से स्वरोजगार को रोजगार का नया आयाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि युवा आज जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रियेटर बनकर देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में प्रत्यक्ष लाभार्थियों की संख्या 2014 में आठ करोड़ थी जो 2017 में 36 करोड़ को पार कर गई है। इतना ही नहीं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सरकार को लगभग 59,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है, जो पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। अकेले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में इस योजना के माध्यम से लगभग 14 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है।

भाजपा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन को कई प्रकार के द्वंद्वों से बाहर निकालने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमने यह सिद्ध करके दिखाया है कि शहरों के विकास के साथ-साथ गांवों का भी विकास किया किया जा सकता है और उद्योगों के साथ-साथ कृषि क्षेत्र का भी विकास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमने जनप्रतिनिधि और अफसरशाही के बीच के द्वंद्व को भी ख़त्म किया है। हमने यह साफ कर दिया है कि पॉलिसी निर्माण का कार्य जन-प्रतिनिधि करेंगे तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी नौकरशाहों की होगी। उन्होंने कहा कि हमने जहां वोट बैंक की परवाह किये बगैर रिफॉर्म्स को भी दृढ़ता के साथ लागू किया है। वहीं कल्याण राज्य के निर्माण के लिए कई जनोपयोगी योजनाओं की भी नींव रखी है। उन्होंने कहा कि जब सरकार नीतियां नहीं बनाती और नीतियों की जरूरत के हिसाब से समयानुकूल परिवर्तन नहीं करती तो अर्थव्यवस्था की गति मंद पड़ना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से नीतिगत फैसले लेने शुरू किये गए। उन्होंने कहा कि अकेले नीति आयोग की रचना ने ही देश के फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में काफी गुणात्मक परिवर्तन किया है - पहले राज्य मदद के लिए वित्त आयोग के पास आया करते थे, अब नीति आयोग राज्यों के पास जाता है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में एजुकेशन हो, इंडस्ट्री हो, इश्यू हो - नीति आयोग ने हर क्षेत्र में एक सकारात्मक भूमिका अदा किया है।

'प्रगति' कार्यक्रम का ख़ास तौर पर जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा

कि मैं इस कार्यक्रम के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि 'प्रगति' कार्यक्रम को जितनी प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी, उतनी नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री जी स्वयं हर 15 दिन में एक बार सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ देश भर में रुके हुए प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं और इसमें आ रही दिक्कतों को दूर कर के इन योजनाओं को गति देते हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की बदौलत देश की अर्थव्यवस्था को काफी गति मिली है। सड़क बनाने की गति लगभग दुगुनी हो गई है। एनवायरनमेंट एंड फ़ॉरेस्ट क्लीयरेंस में पहले 600 दिन लगते थे, अब महज 180 दिन लगते थे, हम इसे और कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पहले कोयले एवं खनिज खदानों की नीलामी के लिए कोई पॉलिसी नहीं थी, लेकिन आज MMDR में संशोधन और पारदर्शी नीलामी की प्रक्रिया के कारण हमारे कार्यकाल में एक भी केस नहीं हुआ है, सारी कोयले खदानें उत्पादन कर रही हैं, यही कारण है कि आज भारत बिजली के क्षेत्र में सरप्लस है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि एफडीआई को सरल बनाने की दिशा में भी मोदी सरकार ने कई कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा कि आपसी सहयोग से नीतिगत फैसलों को क्रियान्वयित करने का सबसे बड़ा उदाहरण जीएसटी का लागू होना है। उन्होंने कहा कि कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि इतने बड़े देश में, विविधताओं, कई सारी राजनीतिक पार्टियों एवं विभिन्न विचारों के चलते जीएसटी भारत में लागू भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर, सभी राज्यों से बात करके हम देश में 'एक राष्ट्र, एक कर' के स्वप्न को साकार करने में सफल हुए। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के पास देश के पश्चिमी हिस्से की तरह देश के पूर्वी हिस्से का विकास नहीं हो पाया और एक ही देश में एक हिस्सा मैनुफैक्चरिंग और दूसरा हिस्सा कंज्यूमर हब बन कर रह गया, लेकिन आज 'जीएसटी' के बाद से आने वाले समय में देश में समान विकास की परिकल्पना साकार हो सकेगी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद हल हो जाने से पूर्वोत्तर के विकास में आ रही बाधाओं को पार करने में अच्छी सफलता प्राप्त होगी।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार लोगों को अच्छे लगने वाले फैसले लेने की जगह लोगों के लिए अच्छे फैसले लेने में यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि हमने नीतिगत निर्णय को वोट बैंक के साथ कभी नहीं जोड़ा। हमने देश के अर्थतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कठोर एवं जरूरी फैसले लेने का काम किया है, विमुद्रीकरण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि डिमोनेटाइजेशन के कारण फॉर्मल इकोनॉमी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मॉरीशस-सिंगापुर-साइप्रस रूट को बंद कर और दोहरे कराधान के करारों का पुनर्मूल्यांकन कर के कालेधन पर नकेल कसने का काम केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उन्होंने कहा कि हमने अपनी दिक्कतों के बावजूद कैसे में राजनीतिक चंदे की सीमा को 2,000 रुपये तक सीमित कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम देश की राजनीतिक एवं चुनावी व्यवस्था में से काले धन को बाहर निकालना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस दिशा में इतना बड़ा प्रयास नहीं किया, जितना गंभीर प्रयास भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम एक ऐसा देश बनाने का प्रयास किया है, जिसमें अगली पीढ़ी को प्रगतिशील एवं भ्रष्टाचार-मुक्त भारत के अंदर विकास करने का मौक़ा मिले और शेष विश्व के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सके।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हमने फिस्कल डेफिसिट को 3% के पास लाकर वित्तीय घाटे को करने में सफलता प्राप्त की है। हमने राज्यों को एम्पावर करके उन्हें देश के विकास में जोड़ा है। उन्होंने कहा कि हमने हर क्षेत्र में दो से तीन गुना वृद्धि करने के बावजूद फिस्कल डेफिसिट को काबू में रखने का सफल प्रयास किया है। शेयर बाजार सूचकांक अब तक के सर्वोच्च स्तर पर है। साथ ही, सरकार ने बैंकों के बैलेंस को भी क्लियर करने का प्रयास किया है। एनपीए के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी रोग को छुपाने से रोग का समाधान नहीं हो सकता,

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार लोगों को अच्छे लगने वाले फैसले लेने की जगह लोगों के लिए अच्छे फैसले लेने में यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि हमने नीतिगत निर्णय को वोट बैंक के साथ कभी नहीं जोड़ा। हमने देश के अर्थतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कठोर एवं जरूरी फैसले लेने का काम किया है, विमुद्रीकरण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। डिमोनेटाइजेशन के कारण फॉर्मल इकोनॉमी बढ़ेगी।

यदि एनपीए की समस्या है तो इसका समाधान किया जाना चाहिए। इसे छुपाने से कोई फायदा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बैलेंस शीट की जगलरी करने से एनपीए की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हम एनपीए को रिकॉर्ड पर लेकर आये हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद अब तक देश के किसी भी नेता में एनपीए को स्पष्ट तरीके से बैलेंस शीट में लाने का साहस नहीं था, जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया है। उन्होंने कहा कि एनपीए को बैलेंस शीट में लाकर बैंकिंग व्यवस्था को सुधारने का बहुत बड़ा कदम मोदी सरकार ने उठाया है। उन्होंने कहा कि एनपीए का एक भी एकाउंट हमारे समय का नहीं है, ये सभी हमें विरासत में मिले हैं। उन्होंने कहा कि स्टार्ट-अप एवं स्टैंड-अप इंडिया से भी देश की अर्थव्यवस्था को काफी गति मिलेगी।

श्री शाह ने कहा कि रोड, रेलवे, पोर्ट, हाउसिंग - इन सभी को लक्ष्य बना कर डेवलपमेंट को मोदी सरकार ने आगे बढ़ाने का काम

किया है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय प्रतिदिन लगभग 69 किलोमीटर के हिसाब से ग्रामीण सड़कों का निर्माण होता था, जबकि आज प्रतिदिन 133 किलोमीटर के हिसाब से हो रहा है। यूपीए के समय 4.3 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से रेल लाइंस बिछाई जाती थी, आज 7.9 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि यूपीए II के पांच वर्षों में रेलवे में जितना निवेश हुआ, उसका दोगुना केवल मोदी सरकार के दो साल के अंदर हुआ। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत ने मोदी सरकार के तीन सालों में काफी प्रगति की है। कोयले और बिजली के क्षेत्र में हम आज सरप्लस हैं, सारे डिस्कॉम को लॉस से बाहर निकाला गया है, बिजली से वंचित 18 हजार गांवों में से 14 हजार गांवों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर लिया गया है। 2018 तक हर गांव और 2022 तक देश के हर घर में बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सागरमाला प्रोजेक्ट्स पूरा होने के बाद बंदरगाहों के विकास से देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आयेगा। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के माध्यम से आने वाले समय में एवियेशन सेक्टर में लगभग दो से तीन गुनी वृद्धि देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश में एयरक्राफ्ट की संख्या में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बनने के पहले देश में ऑप्टिक फाइबर की कुल लेंथ 358 किलोमीटर थी, जबकि आज 2,00000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर डालने का काम समाप्त हो चुका है, हमने तय किया है कि 2022 तक देश के हर गांव को ऑप्टिक फाइबर से जोड़ने का काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाउसिंग क्षेत्र में भी काफी डेवलपमेंट हुए हैं। पिछले तीन साल में 22 लाख घर बनाने का काम शुरू कर दिया गया है और अगले एक साल के अंदर और 22 लाख घर बनाने की शुरुआत कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमने लक्ष्य रखा है कि 2022 तक देश के हर व्यक्ति के पास अपना घर हो। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकारों ने पिछले तीन साल में लगभग 7,000 फैसले किये हैं, जिससे ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में काफी सुधार आया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के इन आर्थिक फैसलों के कारण देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर में काफी वृद्धि हुई है। इंटरेस्ट रेट को 6% तक लाने में हम सफल हुए हैं, सीपीआई (महंगाई) को 5% तक सीमित किया है। उन्होंने कहा कि करेंट एकाउंट डेफिसिट को -4.80 से -0.6 तक लाने में हम सफल हुए हैं। विदेशी मुद्रा भंडार 3.91 बिलियन डॉलर के साथ अब तक के सर्वोच्च शिखर पर है और एफडीआई इनफ्लो 3.7 बिलियन डॉलर से बढ़ कर 6.3 बिलियन डॉलर पहुंचा है। उन्होंने कहा कि आजादी से लेकर केंद्र में मोदी सरकार के गठन होने तक देश में कुल टैक्स पेयर्स की संख्या महज 3.7 करोड़ थी, जबकि मोदी सरकार के तीन साल में ही यह आंकड़ा बढ़ कर 6.3 करोड़ हो गया है, यही बताता है कि देश की आर्थिक विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता क्या है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सबसे बड़ी उपलब्धि देश के सोचने के स्केल में बदलाव लाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण आज दुनिया भर में एक ब्रांड इंडिया की सोच डेवलप हुई है। उन्होंने कहा कि ब्रांड इंडिया के निर्माण का काम सरकार का है, लेकिन इसे एनकैश करने का कम फिक्की और उद्योग जगत से जुड़े संगठनों का है। उन्होंने कहा कि जिन देशों के अंदर किसी एक दशक के अंदर सबसे अधिक औद्योगिक विकास में औद्योगिक संगठनों ने क्या भूमिका निभाई है, इसकी एक स्टडी होनी चाहिए और उसमें हम कहां खड़े हैं, यह देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिक्की जैसे उद्योग संगठनों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कंसोर्टियम बनाना चाहिए, ताकि पेटेंट रजिस्ट्रेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से होने वाले मुनाफे का लाभ देश को मिल सके। उन्होंने कहा कि आज भी दुनिया में कैसे ऐसे छोटे-छोटे देश हैं जहां भारतीय औद्योगिक कम्पनियां इन्वेस्ट करके व्यवसाय कर सकती है। हमें मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने की जरूरत है, हम आज उस जगह पर खड़े हैं जहां भारतीय कम्पनियां नई संभावनाओं को एक्सप्लोर कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत से जुड़े संगठनों को एक अलग डायमेंशन से भी सोचने की जरूरत है। अगर हम यह नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में ब्रांड इंडिया का जितना फायदा होना चाहिए, उतना हमें नहीं मिल पायेगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार देश को 125 करोड़ का मार्केट बनाने का प्रयास कर रही है, यह अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। इस लक्ष्य को हम 'मेक इन इंडिया' के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस पर हमें काफी सारा आर एंड डी करने की जरूरत है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य बहुत सुंदर है। हमें विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार रिफॉर्म्स से भी कई कदम आगे बढ़ कर ट्रांसफॉर्मेशन में यकीन रखती है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य बहुत सुंदर है। हमें विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार रिफॉर्म्स से भी कई कदम आगे बढ़ कर ट्रांसफॉर्मेशन में यकीन रखती है। हम सोच के साथ - साथ कार्यप्रणाली में भी आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहते हैं और सभी फैसले सोच समझकर देश हित में लिए गए हैं। ■

जनसभा, बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश)

जनता को जमानती सरकार से मुक्ति मिलनी चाहिए : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर में बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की आधारशिला रखी। इस दौरान प्रदेश के राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह भी उपस्थित रहे। 750 बिस्तर वाले इस अस्पताल पर करीब 1,350 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। यहां स्वास्थ्य सेवा के अलावा नर्सिंग, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर मेडिकल शिक्षा भी मुहैया होगी। इसके अलावा श्री मोदी ने ऊना में आईआईटी की भी आधारशिला रखी।

एम्स की आधारशिला रखने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बिलासपुर में बनने वाले एम्स से सिर्फ हिमाचल प्रदेश को ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत को फायदा होगा। इससे राज्य की रोजी-रोटी यानी टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने इस दौरान जहां अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया वहीं कांग्रेस सरकार पर भी जमकर प्रहार किया। श्री मोदी ने पूर्व की यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां कई साल से महज 70 करोड़ का एक स्टील प्रॉजेक्ट अटका पड़ा था। उन्होंने कहा कि पहले डिपार्टमेंटों में अलग प्रधानमंत्री होता था। एक सरकार में कई सरकार थीं। रिमॉट कंट्रोल से चलने वाला पीएम अलग था। भाजपा सरकार आने के बाद अटके हुए प्रॉजेक्ट पूरे करने का काम हुआ। अब यहां के लोगों को घर बनाने के लिए सस्ते मूल्यों में सरिया मिलेगा।

उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ दिनों पहले कुछ कांग्रेस के मित्र मेरे पास आए। मैंने उनसे पूछा कि हिमाचल के सीएम जमानत पर बाहर हैं, आप उन्हें हटाकर किसी और को सीएम क्यों नहीं बनाते? तो उन मित्रों ने कहा कि हमारी पूरी पार्टी ही जमानत पर चल रही है।' श्री मोदी ने कहा कि हिमाचल में भी जनता को जमानती सरकार से मुक्ति मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज यहां करीब 1500 करोड़ रुपये के काम को मंजूरी मिली है। कुछ का शिलान्यास हुआ है तो कुछ का लोकार्पण। 1300 करोड़ में बनने वाले एम्स से न सिर्फ हिमाचल को फायदा मिलेगा, बल्कि यहां आने वाले टूरिस्ट और पूरे उत्तर भारत को इसका फायदा होगा। ये एम्स हिमाचलवासियों के लिए तो संजीवनी बनकर आया है, लेकिन टूरिज्म को बढ़ाने में अहम कारक बन सकता है। यह अस्पताल पूरे उत्तर भारत के लिए डिजाइन के हिसाब से स्पेस ऑफ द आर्ट बनेगा। इस अस्पताल में एक साथ 3 हजार लोग काम कर सकेंगे।

उन्होंने इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा और स्वास्थ्य कार्यक्रम इंद्रधनुष की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारे देश में लाखों बच्चे कोई न कोई टीका लगने से छूट जाते हैं। इन बच्चों को बचाने का काम नड्डा जी ने शुरू किया। इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत टीकाकरण का काम कराया। इस सप्ताह फिर से इस योजना के माध्यम से छूट गए बच्चों को टीका लगाया जाएगा। दिवाली से पहले ऐसे बच्चों को टीका लगाना है। इस दौरान श्री मोदी ने भाजपा, आम जनता, राजनीतिक दलों और एनजीओ को ऐसे बच्चों को खोजने को कहा जिनको टीका नहीं लग पाया है। उन्होंने कहा, "ओआरओपी का मामला 40 साल से अटका था। मंडी में अपनी रैली में मैंने ऐलान किया था कि हम इस पर फैसला लेंगे। ओआरओपी में दो किश्त जा चुकी हैं। एक किश्त और जल्द ही दी जाएगी। इससे बजट का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, लेकिन मेरे लिए सेना का जवान प्रथम है।" उन्होंने कहा कि तीन दिन पहले सर्जिकल स्ट्राइक का प्रथम वर्ष मनाया गया। इसमें मीडिया ने अहम भूमिका निभाई।

उन्होंने कहा कि हिमाचल में इन दिनों करीब 13 प्रॉजेक्ट चल रहे हैं। इनमें रेलवे, पेट्रोलियम और अन्य डिपार्टमेंट के प्रॉजेक्ट हैं। भारत सरकार इन प्रॉजेक्ट में 15 हजार करोड़ रुपये लगाएगी, जो व्यवस्था विकसित होगी वह हिमाचल को आगे बढ़ाने में योगदान देगी। स्वच्छता की दिशा में हिमाचल के नागरिकों ने जो काम किया है। वह तारीफ के लायक है। इसके लिए पीएम ने नागरिकों और अधिकारियों को बधाई दी। श्री मोदी ने कहा, "तीन साल हो गए, लेकिन हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। पहले पूछा जाता था कि कितने रुपये गए और अब पूछा जाता है कि कितने रुपये आए।" उन्होंने कहा कि सड़क और बिजली किसी भी राज्य के विकास में सबसे ज्यादा अहमियत रखती हैं। अगर ऐसा होगा तो टूरिस्ट भी हिमाचल में खूब आएगा। हमने 1000 दिन का अभियान उठाया है कि एक गांव भी ऐसा न बचे, जहां बिजली न हो। अगर कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता होगा, तो भी उसे बिजली का कनेक्शन मिलना चाहिए। हमारे पास अब भी चार करोड़ परिवार ऐसे हैं, जिन्हें बिजली नहीं मिली है। सौभाग्य योजना के तहत इन 4 करोड़ परिवारों को मुफ्त में कनेक्शन दिया जाएगा। ■

पत्र-पत्रिकाओं से...

बदलाव की ओर

एक अच्छा विचार धीरे-धीरे कदम बढ़ा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि वह साल भर के भीतर इस स्थिति में होगा कि देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवा सके। आयोग के इस बयान से उस अभियान को बल मिला है, जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के करीब है। उन्होंने एक से ज्यादा बार यह कहा है कि हमें रोज-रोज चुनाव के चक्कर से बचने के लिए ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो जाएं। इस पर कई मंत्रालयों की राय भी मांगी गई थी, वे भी इसके समर्थन में हैं। कुछ नागरिक संगठन तो न जाने कब से यह मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात अनसुनी ही की जाती रही, अब उन्हें भी उम्मीद बंधी होगी। भारत ने लोकतंत्र को जिस ढंग से अपनाया है, उससे राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से लोकतंत्र उसकी एक ताकत बन गया है।

- जनसता (7 अक्टूबर)

पुलिस की आंतरिक संरचना में बदलाव

पुलिस सुधार के लिए राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए का पैकेज देने का केंद्र का एलान स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री पुलिस को चुस्त दुरुस्त, आधुनिक और स्मार्ट देखना चाहते हैं और उनकी इच्छा मुनासिब है।

- दैनिक भास्कर (२९ सितंबर)

बढ़ती हुई मुहिम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता के महत्व को स्वीकार किया है और इसे अपना प्रमुख अजेंडा बनाया है। देश में स्वच्छता को लेकर बने माहौल का ही असर है कि आज गांवों में कई लड़कियों ने अपनी ससुराल में शौचालय बनाने पर जोर दिया और इसके लिए डटी रहीं। कुछ ने तो लड़के के यहां शौचालय न होने के कारण शादी तक से इनकार कर दिया। गांवों में लोग अब खुद आगे आकर शौचालय बनवा रहे हैं। यह परिवर्तन निरंतर प्रचार की ही देन है।

- नवभारत टाइम्स (२ अक्टूबर)

आतंक के खिलाफ

पिछले कुछ समय के दौरान आम आबादी पर बमबारी से लेकर सैन्य शिविरों तक पर हमले करने वाले आतंकियों को सुरक्षा बलों की चौकसी की वजह से मुंह की खानी पड़ी और उनमें से कई मारे भी गए। इसी कड़ी में सोमवार को एक बड़ी कामयाबी तब मिली, जब शोपियां इलाके में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में प्रमुख आतंकी जाहिद सहित हिज्बुल मुजाहिदीन के तीन आतंकियों को मार गिराया। इसके साथ ही बारामूला जिले में एक अन्य मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद का एक शीर्ष कमांडर सुरक्षा बलों के हाथों मारा गया।

- जनसता (11 अक्टूबर)

जीएसटी में सुधार

जीएसटी काउंसिल ने ऐसे संशोधनों का ऐलान किया, जिनकी जरूरत जीएसटी लागू होने के बाद से ही महसूस की जाने लगी थी। वित्तमंत्री के मुताबिक, जीएसटी के तीन महीनों के अनुभव और लोगों से मिले फीडबैक के आधार पर ये बदलाव किए गए हैं। सरकार अपने अनुभव से सबक ले और लोगों के फीडबैक के आधार पर नीतियों में बदलाव करे, यह किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छी बात ही कही जाएगी।

- नवभारत टाइम्स (अक्टूबर 9, २017)

स्फुट विचार...

चलिए सुबह का पहला काम ये करें कि इस दिन के लिए संकल्प करें कि- मैं दुनिया में किसी से डरूंगा नहीं। मैं केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव ना रखूं। मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए, मैं सभी कष्टों को सह सकूं।

- महात्मा गांधी

देश के प्रति निष्ठा सभी निष्ठाओं से पहले आती है और यह पूर्ण निष्ठा है, क्योंकि इसमें कोई प्रतीक्षा नहीं कर सकता कि बदले में उसे क्या मिलता है।

- लाल बहादुर शास्त्री

हम निर्बल से निर्बल व्यक्ति तक पहुंचे। हमारी भारतीय जनता पार्टी का यह एक राजनीतिक नारा मात्र नहीं है। यह हमारे सामाजिक दर्शन, जो एकात्ममानववाद के मूल में है, में रचा बसा है।

- कुशाभाऊ ठाकरे

कंधे-से-कंधा लगाकर, कदम-से-कदम मिलाकर हमें अपनी जीवन-यात्रा को ध्येय-सिद्धि के शिखर तक ले जाना है। भावी भारत हमारे प्रयत्नों और परिश्रम पर निर्भर करता है। हम अपना कर्तव्य पालन करें, हमारी सफलता सुनिश्चित है।

- अटल बिहारी वाजपेयी

प्रस्तुतिः पंकज आनंद

हमारे सम्मानित आजीवन सदस्यगण

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत
श्री अमित शाह
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री अरुण जेटली
केंद्रीय वित्त एवं रक्षा मंत्री
श्री राधा मोहन सिंह
केंद्रीय कृषि मंत्री
श्री प्रकाश जावडेकर
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री जगत प्रकाश नड्डा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
श्रीमती मेनका संजय गांधी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री
श्री अर्जुन राम मेघवाल
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट राज्यमंत्री
श्री विष्णुदेव साय
केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री
श्री बाबुल सुप्रियो
केंद्रीय भारी उद्योग राज्यमंत्री
श्री मनोहर पर्रिकर
मुख्यमंत्री, गोवा

श्री भूपेन्द्र यादव, सांसद
भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री
श्री अरुण सिंह
भाजपा राष्ट्रीय महासचिव
श्री शांता कुमार, सांसद
पूर्व मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश
श्री गोपाल नारायण सिंह
सांसद (राज्यसभा)
डॉ. गोकाराजू गंगा राजू
सांसद (लोकसभा)
श्री महेश पोद्दार
सांसद (राज्यसभा)
श्री अनिल शिरोले
सांसद (लोकसभा)
श्री मनोज राजोरिया
सांसद (लोकसभा)
श्री रवींद्र कुमार राय
सांसद (लोकसभा)
श्री दिलीप कुमार गांधी
सांसद (लोकसभा)
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल
राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अपने गृहनगर वडनगर (गुजरात) की यात्रा के दृश्य

उत्साहित व भावानुभूति से भरा विशाल जन–समुदाय

भव्य स्वागत

द्वारकाधीश मंदिर परिसर में

वडनगर में हटकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा–अर्चना करते हुए

द्वारका में किसान रैली का दृश्य, जहां पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को देश को समर्पित किया

अनेक विकास परियोजनाओं को समर्पित करने के बाद बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में विशाल रैली को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2015-17
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2015-17

1 राष्ट्र कर बाजार

"अच्छा और सरल कर (जीएसटी) अब और सरल होकर हमारे नागरिकों के हितों की रक्षा और अर्थव्यवस्था की मजबूती सुनिश्चित करेगा"

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

देशवासियों को दिवाली का उपहार

बेहतर और सरल जीएसटी

- सक्रिय जनभागीदारी से जीएसटी बना अब सबके लिये अनुकूल
- छोटे एवं मध्यम वर्ग के कारोबारियों का व्यापार अब और आसान
- लघु उद्यमियों के लिए अनेक नई संभावनाएं और अवसर
- निर्यातकों को बड़ी और महत्वपूर्ण राहत
- रोज़मर्रा के उपयोग की वस्तुओं, कपड़ा और उत्पादन के क्षेत्र में दरों में कटौती
- किसानों और गरीबों को बड़ा लाभ

हम सब मिलकर बनायेंगे - स्वच्छ और मज़बूत अर्थव्यवस्था वाला नया भारत

कई तरह के धागे, डीजल इंजन और पंप के पुर्ज़े समेत 27 वस्तुओं पर टैक्स हुआ कम	कंपोजीशन स्कीम का टर्नओवर दायरा 75 लाख से बढ़कर अब 1 करोड़	टीडीएस / टीसीएस प्रावधान अब 1 अप्रैल, 2018 से लागू किए जाएंगे	माल परिवहन एजेंसियों द्वारा अपंजीकृत व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाओं पर छूट	ई-वे बिल प्रणाली 1 जनवरी, 2018 से क्रमबद्ध तरीके से लागू की जाएगी
सीजीएसटी सेक्शन 9(4) / आईजीएसटी एक्ट सेक्शन 5(4) के अंतर्गत रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म 31 मार्च, 2018 तक स्थगित	1.5 करोड़ टर्नओवर तक करदाताओं को सामान के लिए मिलने वाली अग्रिम राशि पर उसी समय जीएसटी भुगतान की अब आवश्यकता नहीं	अंतरराज्यीय सेवा प्रदाताओं समेत 20 लाख टर्नओवर से कम वाले सभी सेवा प्रदाताओं को अब पंजीकरण से छूट	1.5 करोड़ टर्नओवर तक वाले व्यापारियों को अब सिर्फ तिमाही रिटर्न फाइल करना होगा	छूट-प्राप्त सेवा प्रदान करने वाले सभी कारोबारी अब कंपोजीशन स्कीम के पात्र

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों
के वाणिज्यिक कर विभाग

अधिक जानकारी के लिए
www.cbec.gov.in | www.cbec-gst.gov.in
www.gst.gov.in

जीएसटी संबंधित किसी भी जानकारी के लिए : @askGST_GoI पर ट्वीट करें

हेल्प डेस्क : 0120 - 4888 999 | 1800 1200 232